सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 166, नई दिल्ली । सोमवार, 26 अगस्त 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

03 लालबाग का राजा दिल्ली गणपति महोत्सव का हुआ भूमि पूजन।
06 तालिबान कुशासन के 3 साल
08 सड़क सुरक्षा पर मंडराता खतरा

क्या दिल्ली परिवहन विभाग जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभा रहा हैं या फिर कर रहा है ढोंग और सिर्फ कागजी खानापूर्ति, बड़ा सवाल?

संजय बाटला

नई दिल्ली। परिवहन विभाग दिल्ली के आला अधिकारी ने यह चरितार्थ कर दिखाया की तकनीकी कार्यों के लिए तकनीकी अधिकारियों की कोई आवश्यकता नहीं तकनीकी कार्य गैर तकनीकी अधिकारी तकनीकी अधिकारी से बेहतर कर सकते हैं। आपकों पुराने जमाने मे जो बुजुर्ग कहते थे वह तो याद ही होगा **"पढ़े लिखे व्यक्ति से अधिक अनुभव गुढे हुए व्यक्ति के पास होता है"** क्योंकि पढ़ा व्यक्ति का अनुभव कार्य क्षेत्र में कम और गुढे व्यक्ति का ज्यादा होता है। इस बात को चरितार्थ कर दिखाया परिवहन विभाग के आला अधिकारी ने "गैर तकनीकी अधिकारियों को तकनीकी पदो पर और परिवहन विभाग में जो कुछ तकनीकी अधिकारी बचे हैं उन्हें गैर तकनीकी पदो पर नियुक्त कर"। अब आप इसे दूसरी भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं " "किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति का डॉक्टर से नही एक परचून की दुकान चलाने वाला भी कर सकता हैं या फिर तकनीकी/ बड़ी शिक्षा जैसे आईएएस/ आईपीएस/ मेडिकल/इंजीनियरिंग इत्यादि की पढ़ाई की जरूरत नहीं वह तो आप बिना शिक्षक या अनपढ़ से पढ़कर कर सकते हैं। इसी लिए प्रवर्तन अधिकारी के पद पर भी अन्य राज्यों ने तकनीकी अधिकारियों को नियुक्त किया हुआ है पर दिल्ली भारत देश की राजधानी में गैर तकनीकी अधिकारियों को नियुक्त कर रखा है। **यहां आपकी जानकारी हेतु एक ही बात बताना चाहूंगा जिस अधिकारी को असली और नकली वाहन के चेसिस नंबर की पहचान नहीं वह अधिकारी गलत/ चोरी के वाहन/ नंबर बदल कर चल रहे वाहनों को कैसे पकड़ेगा और इसी का फायदा आज दिल्ली में सुरक्षा में सेंध लगाने वाले ले रहे हैं।**

आपकी जानकारी हेतु आपकों अवगत करा दें विदेशी और देश के नागरिक जो हवाई वाहन (हवाई जहाज) सेवा का उपयोग करते हैं और वाहन से एयरपोर्ट के गेट तक पहुंचने के लिए जिन वाहनों में बैठाए जाते है उनमें से अधिकांश वाहन एमवी रूल/ एमवी एक्ट के अनुसार अनफिट है और उनका पंजीकरण नियम अनुसार रद्द है पर परिवहन विभाग के आला अधिकारी की कार्यशैली के बल पर लगातार चल रहे हैं और उन्हें चलाने वाले को भी कोई और किसी से डर नहीं लगता।

आपकी जानकारी हेतु याद करवा दू की निर्भया हादसे के बाद महिला सुरक्षा के प्रति जो भी आदेश जारी हुए उन्हें जान बुझकर कर परिवहन विभाग के आला अधिकारी लागू नहीं कर रहे।

दिल्ली भारत देश की राजधानी है और दुनिया भर के पर्यटक और सभी देशों के गणमान्य व्यक्ति यहां आते रहते हैं जिस कारण दिल्ली में सुरक्षा की व्यवस्था भारत देश के अन्य राज्यो से अधिक की सदैव आवश्यकता होती है और इसके अलावा उन्हें समयानुसार सुरक्षित वाहन सेवा उपल्ब्ध रहे इसकी ज़िम्मेदारी दिल्ली परिवहन विभाग की है। यहां प्रश्न यह उठता है की क्या दिल्ली परिवहन विभाग अपनी यह जिम्मेदारी सही ढंग से निभा रहा हैं या फिर सिर्फ कागजी खानापूर्ति कर रहा हैं।

जन्माष्टमी पर शाम छह बजे निकलेगी शोभा यात्रा, दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी

दिल्ली में जन्माष्टमी के त्योहार को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। कई प्रमुख मंदिरों के आसपास दोपहर 2 बजे से सड़क पर प्रतिबंध रहेगा। मंदिर मार्ग काली बाड़ी मार्ग बाबा खड़क सिंह मार्ग बंगला साहिब मार्ग गोल चक्कर गोल मार्केट गोलचक्कर जीपीओ शहीद भगत सिंह मार्ग और पेशवा रोड का इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई है।

नई दिल्ली। दिल्ली में जन्माष्टमी के त्योहार को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बिरला मंदिर समिति द्वारा शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बैंड, रथ और झांकियों के साथ बड़ी संख्या में सैकड़ों श्रद्धालु भाग लेंगे। ये शोभा यात्रा शाम छह बजे से शुरू होगी। इसे ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने तैयारी पूरी करते हुए एडवाइजरी जारी की है।

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, काली बाड़ी मार्ग स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर, अमर कॉलोनी स्थित इस्कॉन मंदिर, द्वारका सेक्टर-13 स्थित इस्कॉन मंदिर, पंजाबी बाग जन्माष्टमी पार्क, प्रीत विहार स्थित गुफावाला मंदिर, छतरपुर स्थित आद्य कात्यानी शक्ति पीठ और हरि नगर स्थित संतोषी माता मंदिर में बड़े आयोजन किए जाएंगे। ऐसे में दोपहर दो बजे से सड़क पर प्रतिबंध रहेगा।

इसके साथ ही गोलचक्कर शंकर रोड मंदिर मार्ग तक मंदिर लेन पर किसी भी वाहन को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। शिवाजी स्टेडियम से मंदिर मार्ग की तरफ जाने वाली बसों को पंचकुइयां रोड या गोलचक्कर जीपीओ की ओर मोड़ा जाएगा। वहीं, पंजाबी बाग स्थित जन्माष्टमी पार्क के समीप भी आवश्यकता अनुसार डाइवर्जन किया जाएगा।

इन रास्तों का नहीं करें इस्तेमाल

मंदिर मार्ग, काली बाड़ी मार्ग, बाबा खड़क सिंह मार्ग, बंगला साहिब मार्ग, गोल चक्कर गोल मार्केट, गोलचक्कर जीपीओ, शहीद भगत सिंह मार्ग और पेशवा रोड का इस्तेमाल न करने की ट्रैफिक पुलिस ने सलाह दी हैं।

भारी वाहनों को किया जाएगा डायवर्ट

कैप्टन गौड़ मार्ग और संत नगर के बीच इस्कान मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता केवल पैदल यात्रियों के लिए खुला रहेगा। वाहन चालक अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कैप्टन गौड़ मार्ग और आउटर रिंग रोड का उपयोग कर सकेंगे।

इसके अलावा ओखला मेट्रो स्टेशन से इस्कान की ओर आने वाले कैप्टन गौड़ मार्ग की एक तरफ सोमवार सुबह आठ बजे से आवश्यकतानुसार भारी वाहनों का डायवर्जन किया जाएगा। आउटर रिंग रोड से आने वाले वाहनों को आश्रम चौक के लिए सीधे मोदी मिल फ्लाईओवर की तरफ भेजा जाएगा।

दिल्ली से भोपाल आने-जाने वाले यात्री ध्यान दें!

6 से 15 सितंबर तक शान-ए-भोपाल ट्रेन नहीं चलेगी, वंदे भारत भी रहेगी कैंसल

उत्तर रेलवे के दिल्ली रेल मंडल में पलवल स्टेशन पर चल रहे कार्य के कारण कई ट्रेनें निरस्त व परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। इनमें भोपाल रेल मंडल की भी चार ट्रेनें शामिल हैं। भोपाल एक्सप्रेस को दोनों ओर से सितंबर में जहां दस दिन के लिए निरस्त किया गया है वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस भी 17 सितंबर को निरस्त रहने वाली है।

नई दिल्ली। उत्तर रेलवे के पलवल रेलवे स्टेशन पर रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए प्री-नॉन और नान-इंटरलाकिंग कार्य किया जा रहा है। यह कार्य दिल्ली रेल मंडल के पलवल और न्यू पृथला यार्ड के बीच रेल कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए किया जा रहा है। रेल मार्ग पर चल रहे कार्य के कारण भोपाल मंडल से होकर गुजरने वाली चार ट्रेनें अलग-अलग तारीखों में निरस्त रहेंगी। इसमें रानी कमलापति से निजामुद्दीन तक जाने वाली

शान-ए-भोपाल एक्सप्रेस छह से 15 सितंबर तक और वंदे भारत भारत एक्सप्रेस 17 सितंबर को निरस्त रहेगी। साथ ही निजामुद्दीन-जबलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेगी।

इन ट्रेनों को किया गया निरस्त

ट्रेन 12155-56 रानी कमलापति-निजामुद्दीन भोपाल एक्सप्रेस प्रारंभिक स्टेशन से दोनों दिशाओं में 6 से 15 सितंबर तक निरस्त रहेगी।

ट्रेन 20171-72 रानी कमलापति-निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस प्रारंभिक स्टेशन से दोनों दिशाओं में 17 सितंबर को निरस्त रहेगी।

शॉर्ट टर्मिनेट ट्रेन

ट्रेन 12192 जबलपुर-निजामुद्दीन श्रीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस 5 से 16 सितंबर तक आगरा कैंट स्टेशन पर शार्ट टर्मिनेट रहेगी। ट्रेन 12191 निजामुद्दीन-जबलपुर श्रीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस 6 से 17 सितंबर तक आगरा कैंट स्टेशन से प्रारंभ होगी।

इस ट्रेन का मार्ग रहेगा परिवर्तित

ट्रेन 12191 निजामुद्दीन-जबलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 29, 30, 31 अगस्त, 01, 02, 03, 04, 05 सितंबर को परिवर्तित मार्ग वाया गाजियाबाद-मथुरा-आगरा कैंट होकर गंतव्य को जाएगी।

जखीरा फ्लाईओवर पर बस में लगी आग, ड्राइवर की सूझबूझ से सभी यात्री सुरक्षित

दिल्ली के मध्य जिले के जखीरा फ्लाईओवर पर रविवार शाम एक बड़ी दुर्घटना टल गई। चलती कलस्टर बस में अचानक आग लग गई लेकिन चालक और कंडक्टर की सूझबूझ से सभी यात्री सुरक्षित उतर गए। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की दो गाड़ियां वहां पहुंची। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की जांच जारी है।

नई दिल्ली। मध्य जिले के जखीरा फ्लाईओवर पर रविवार शाम एक बड़ा हादसा होने टल गया। जखीरा फ्लाईओवर पर चलती कलस्टर बस में अचानक आग लग गई। चालक और कंडक्टर ने पहले खुद ही आग पर काबू पाने का प्रयास किया। लेकिन आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि जैसे ही इंजन से धुआं निकलना शुरू हुआ चालक ने समझदारी दिखाते हुए बस को रोक दिया और आनन-फानन में बस से

सवारियों को उतारा गया।

जब चालक और कंडक्टर के प्रयास के बाद आग नहीं बुझी तो मामले की सूचना पुलिस व दमकल विभाग को दी गई। खबर मिलते ही नजदीकी दमकल केंद्र से दमकल की दो गाड़ियां वहां पहुंची। तब तक आग ने पूरी बस को चपेट में ले लिया था। करीब आधे घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। माना जा रहा है कि इंजन में आग लगने से बस में आग लगी, मामले की जांच जारी है।

बस में अचानक धुआं निकला तो उसने बस रोक दी

जानकारी के अनुसार रविवार शाम करीब 7.30 बजे पुलिस व दमकल विभाग को सूचना मिली कि जखीरा फ्लाईओवर के पास बस में आग लग गई है। खबर मिलते ही पुलिस व दमकल विभाग मौके पर पहुंचा। बस आनंद पर्वत से पंजाबी बाग की ओर जा रही थी। चालक ने बताया कि बस में अचानक धुआं निकला तो उसने बस रोक दी।

इंजन से पहले धुआं बाद में आग की लिपटे निकलने लगी। बस में मौजूद अग्निशमन सिलिंडर से आग को बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं बनी। इस दौरान सभी सवारियां भी बस से उतर गई। देखते ही देखते आग पूरी बस में फैल गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने करीब आठ बजे आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

PUC प्रमाणित वाहन भी दिल्ली-गुरुग्राम में फैला रहे प्रदूषण, जांच से नहीं हो पाती पॉल्यूशन की सटीक पहचान

आइसीसीटी द्वारा दिल्ली और गुरुग्राम में एक लाख 11 हजार 712 वाहनों पर अध्ययन किया गया है। इसमें यह बात सामने आई है कि पीयूसी प्रमाणित वाहन भी सड़कों पर अधिक प्रदूषण फैला रहे हैं। पीयूसी जांच से वाहनों के पॉल्यूशन की सटीक पहचान नहीं हो पाती है। स्वच्छ ईंधन सीएनजी से चलने वाले वाहन भी सड़कों पर निर्धारित मानक से 14.2 गुना तक अधिक प्रदूषण फैला रहे हैं।

नई दिल्ली। सड़क पर फर्राटा भरते वाहनों के पास पीयूसी (पल्युशन अंडर कंट्रोल) प्रमाणपत्र हो, तो मान लिया जाता है कि उस वाहन से खास प्रदूषण नहीं हो रहा है। हाल में आइसीसीटी (इंटरनेशनल काउंसिल आन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन) द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि पीयूसी प्रमाणित वाहन भी सड़कों पर मानक से अधिक प्रदूषण फैला रहे हैं।

एक लाख 11 हजार 712 वाहनों का हुआ अध्ययन

स्वच्छ ईंधन के रूप में स्वीकृत सीएनजी से चलने वाले वाहन भी धुएं में मानक से अधिक प्रदूषक तत्व छोड़ रहे हैं। आइसीसीटी ने दिसंबर 2022 से अप्रैल 2023 के बीच दिल्ली और गुरुग्राम में 20 जगहों पर एक लाख 11 हजार 712 वाहनों का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में दिल्ली के परिवहन विभाग व गुरुग्राम उपायुक्त कार्यालय ने भी सहयोग किया।

अध्ययन में शामिल सभी लोकेशन पर 65 दिन तक रिपोर्ट सेंसिंग तकनीक से वाहनों से निकलने वाले धुएं में नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रो कार्बन, पार्टिकुलेट मैटर (पीएम), अल्ट्रावायलेट स्मोक की जांच की गई। वाहनों में दोपहिया, तिपहिया, निजी कार, टैक्सी, सामान ढोने वाले हल्के व्यवसायिक वाहन, बस व ट्रक शामिल थे।

व्यवसायिक वाहनों से ज्यादा हो रहा प्रदूषण

इस अध्ययन में 89 प्रतिशत वाहन बीएस चार व बीएस छह इंजन वाले शामिल थे। अध्ययन में पाया गया कि निजी वाहनों की तुलना में तिपहिया ऑटो, टैक्सी, हल्के व्यवसायिक वाहन व बसों से प्रदूषण अधिक हो रहा है। सभी प्रकार के वाहनों से नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन मानक से 1.5-14.2 गुना अधिक पाया गया।

बीएस छह के चारपहिया वाहनों की श्रेणी में निजी कार व टैक्सी की तुलना में हल्के व्यवसायिक वाहनों से नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन पांच गुना व दोगुना अधिक पाया गया। कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन क्रमशः सात गुना व छह गुना अधिक पाया गया। हाइड्रो कार्बन का उत्सर्जन क्रमशः पांच गुना व चार गुना अधिक पाया गया।

इसी तरह निजी कार की तुलना में टैक्सी से प्रदूषक तत्वों का उत्सर्जन अधिक पाया गया। कार की तुलना में ऑटो व तिपहिया वाहनों से उत्सर्जन पाया गया। बीएस चार के हल्के व्यवसायिक वाहनों से नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन 25 गुना अधिक पाया गया।

बीएस तीन वाहनों से नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन 1.9 गुना, बीएस चार के वाहनों से 3.2 गुना व बीएस छह वाहनों के से डेढ़ गुना अधिक पाया गया। बीएस तीन के वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन 1.2 गुना व बीएस चार के वाहनों से 2.4 गुना अधिक उत्सर्जन पाया गया।

CNG वाहनों के धुएं में नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन अधिक

अध्ययन में कहा गया है कि सीएनजी को एक स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन माना जाता है। फिर भी सीएनजी से चलने वाले वाहनों के धुएं में नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन अधिक पाया गया। सीएनजी से चलने वाले हल्के व्यवसायिक वाहनों से नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन मानक से 14.2 गुना और टैक्सियों से चार गुना अधिक पाया गया।

लिहाजा अध्ययनकर्ता प्रदूषण जांच में रिमोट सेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल करने पर जोर दे रहे हैं। आइसीसीटी भारत के प्रबंध निदेशक अमित भट्ट ने कहा कि पहली बार इस तरह का अध्ययन किया है। इसलिए वाहनों की प्रदूषण जांच की मौजूदा व्यवस्था पर विचार किए जाने की जरूरत है।

अध्ययन में शामिल वाहनों के आंकड़े

अध्ययन में शामिल वाहन- 1,11,712
कार- 90 प्रतिशत
निजी कार- 75.4 प्रतिशत
टैक्सी- 14.4 प्रतिशत
दोपहिया व तिपहिया वाहन- छह प्रतिशत
हल्के व्यवसायिक वाहन- 2.5 प्रतिशत
बसें- 1.3 प्रतिशत
ट्रक- 0.2 प्रतिशत
विभिन्न ईंधन से चलने वाले अध्ययन में शामिल वाहन
पेट्रोल- 45 प्रतिशत
सीएनजी- 32 प्रतिशत
डीजल- 23 प्रतिशत
विभिन्न बीएस मानकों वाले वाहनों की संख्या
बीएस एक- 0.5 प्रतिशत
बीएस दो- 2.5 प्रतिशत
बीएस तीन- 8 प्रतिशत
बीएस चार- 55.5 प्रतिशत
बीएस छह- 33.5 प्रतिशत

अध्ययन में शामिल पेट्रोल, डीजल व सीएनजी से चलने वाले बीएस तीन, बीएस चार व बीएस छह इंजन वाले वाहनों की संख्या

वाहनों के इंजन के मानक	पेट्रोल	डीजल	सीएनजी
बीएस तीन	41	21	38
बीएस चार	39	26	35
बीएस छह	55	17	28

जन्माष्टमी पर रख रहे हैं व्रत तो बीपी, शुगर को नियंत्रण में रखने के लिए डॉक्टर के बताए हुए सुझावों का पालन करें

जन्माष्टमी का पर्व कल यानी 26 अगस्त 2024 को पूरे भारत में मनाया जा रहा है, इस दौरान उत्सव की मिठाइयां खाते समय और उपवास करते समय, हम सभी भूल ही जाते हैं कि को अधिक खाने से अप्रत्याशित स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप डॉक्टर के बताए हुए टिप्स को फॉलो करेंगे तो जन्माष्टमी का व्रत बेहतर तरीके से रख पाएंगे।

कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अधिकांश लोग दिन भर का उपवास रखते हैं। कई लोग पूरे दिन पाग सहित कई प्रकार के मीठे व्यंजन बनाते और खाते हैं। आपको शायद ही कोई ऐसा घर मिलेगा जहां मेवा पाग, गिरी पाग और धनिया पंजीरी न बनाई जाती हो। यदि कोई इस डॉक्टर द्वारा सुझाई गई इन पांच बातों को ध्यान में रखता है, तो वह अंतहीन नट्स खा सकता है और इस खास दिन को अच्छे से मना सकता है।

डॉक्टर के मुताबिक, पूरे दिन उपवास करने और उत्सवों में भाग लेने के बाद, लोग अक्सर स्वास्थ्य समस्याओं के साथ अस्पतालों में पहुंचते हैं। इसलिए पहले से ही सावधानी बरतना बेहतर है।

सही मिठाई चुनें

वैसे तो मिठाई के बिना जन्माष्टमी का महत्व अधूरा है, लेकिन इसे अधिक मात्रा में खाना हानिकारक हो सकता है। मिठाइयां न केवल रक्त शर्करा के स्तर में असंतुलन पैदा कर सकती हैं, बल्कि अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को भी जन्म दे सकती हैं। त्योहार के दौरान घी से बनी मिठाइयां खाने से बेहतर है कि दूध से बनी मिठाइयां खाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि दूध से बनी मिठाइयों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और ये हमारे शरीर को कम नुकसान पहुंचाती हैं।

व्रत के दौरान तले हुए भोजन से परहेज करें

व्रत के बाद पूरी, पकवान, पकौड़े जैसी तली हुई चीजों के सेवन से हर कीमत पर बचना चाहिए क्योंकि इससे मोटापा और हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। तला हुआ भोजन न केवल कैलोरी बढ़ाता है बल्कि डिहाइड्रेशन और कब्ज जैसी पेट की समस्याएं भी पैदा कर सकता है।

व्रत के दौरान भोजन की मात्रा सीमित करें

त्योहारों के बीच हम अक्सर जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। व्रत के दौरान भी हम कुछ न कुछ खाते रहते हैं। कई बार हम सुबह घंटों भूखे रहने के बाद शाम को बहुत ज्यादा खा लेते हैं। इससे पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए, व्यक्ति को अपने द्वारा खाए जाने वाले भोजन की मात्रा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है।

संतुलित आहार बनाए रखें

चाहे उपवास हो या कोई अन्य, किसी को भी अपने आहार में सभी पोषक तत्वों को शामिल करना नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने आहार में फल, सब्जियां, प्रोटीन और दूध जैसे खाद्य पदार्थों को शामिल करना सुनिश्चित करना चाहिए।

हाइड्रेटेड रहें

दिन भर उत्सव में डूबे रहने के दौरान हमें पानी पीना नहीं भूलना चाहिए। पर्याप्त पानी पीने से हमारा शरीर हाइड्रेटेड रहता है और हम बिना किसी परेशानी के जन्माष्टमी का आनंद ले सकते हैं।

365 दिन बाद बनने जा रहा है नीचभंग राजयोग, इन राशियों खुलेगी किस्मत, शुक्रदेव बरसाएंगे कृपा

दित्यांशी भदौरिया

प्रेम, धन और सुख-समृद्धि के कारक ग्रह शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करके नीचभंग राजयोग बनाने जा रहे हैं। शुकदेव सितंबर में अपनी नीच राशि कन्या में गोचर करेंगे। जिससे नीचभंग राजयोग का निर्माण होगा। इससे 3 राशि को जातकों के लिए शुरु होंगे अच्छे दिन। जाने कौन-सी हैं ये 3 राशियां।

ज्योतिष के अनुसार, जब ग्रह एक से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो शुभ योग और राजयोग का निर्माण होता है। इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन अथवा तमाम देश-दुनिया पर भी पड़ता है। प्रेम, धन, एश्वर्य और सुख-समृद्धि के कारक ग्रह शुकदेव सितंबर में अपनी नीच राशि कन्या में गोचर करेंगे। जिससे नीचभंग राजयोग का निर्माण होगा। इसका असर सभी राशियों पर देखने को मिलेगा। हालांकि, इन 3 राशियों की किस्मत चमक सकती है। इसके साथ ही इन लोगों को आकस्मिक धन लाभ और करियार-कारोबार में सफलता मिल सकती है। आइए जानते हैं कौन हैं ये लकी राशियां।

कन्या राशि

कन्या राशि के जातको के लिए नीचभंग राजयोग काफी शुभ साबित होने वाला है। क्योंकि शुक्र ग्रह कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस दौरान आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। इसके साथ ही शादीशुदा लोगों का जीवनसाथी के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। आपके जीवनसाथी की इस दौरान तरक्की होगी। आप परिवार के साथ अच्छा समय बीताएंगे। इस दौरान आप एक साथ कई सारे काम करने में माहिर होंगे। इसका लाभ आपको मिलेगा। वहीं, अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव आ सकता है।

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए नीचभंग राजयोग फलदायी सिद्ध होगा। क्योंकि धन का दाता शुक्र आपकी गोचर कुंडली के नवम भाव पर संचरण करेंगे। इस अवधि में आपका भाग्योदय होगा। इसके साथ ही आय के स्रोत बढ़ेंगे। किसी नए काम की शुरुआत हो सकती है। आपके धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। कार्य के चलते यात्रा भी कर सकते हैं। इसके साथ ही इस दौरान आप किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।

धनु राशि

धनु राशि के नीचभंग राजयोग काफी शुभ होने वाला है। वो इसलिए शुक्र ग्रह आपकी राशि से कर्म भाव पर संचरण करने जा रहे हैं। इसलिए इस दौरान आपके व्यवसाय में तरक्की होगी। इसके साथ ही नौकरीपेशा वाले लोगों के लिए यह गोचर काफी लकी साबित होगा। आप अपने करियर में नई ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। नौकरी मे प्रमोशन का योग बन रहा है। वहीं व्यापरियों को धन लाभ हो सकता है। इस समय आप कारोबार का विस्तार कर सकते हैं।

नॉन-स्टिक कुकवेयर पर बना रहे हैं खाना तो इन बातों का रखें ध्यान

मिताली जैन

अक्सर यह देखने में आता है कि हम खाली पैन को प्रीहीट करते हैं। कास्ट आयरन या स्टील के बर्तनों में अक्सर ऐसा किया जाता है। लेकिन नॉन-स्टिक पैन को बिना किसी तेल के तेज़ आंच पर रखने पर अस्वास्थ्यकर धुआं निकलता है।

नॉन-स्टिक कुकवेयर का इस्तेमाल करना आज के समय में हर किचन में किया जाने लगा है। सुबह के समय जब परफेक्ट स्क्रैम्बल एग या सनी साइड अप बनाना हो या फिर आप चीला बनाने की तैयारी कर रहे हों तो नॉन-स्टिक कुकवेयर आपके काम को काफी आसान बनाता है। इन्हें साफ करना भी काफी आसान होता है। हालांकि, यह जल्दी से खराब ना हो, इसलिए इन्हें सही तरह से इस्तेमाल करना और केयर करना बेहद जरूरी होता है। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे ही आसान टिप्स के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें फॉलो करके आप नॉन-स्टिक कुकवेयर में अधिक बेहतर तरीके से कुकिंग कर सकते हैं-

खाली पैन को ना करें प्रीहीट

अक्सर यह देखने में आता है कि हम खाली पैन को प्रीहीट करते हैं। कास्ट आयरन या स्टील के बर्तनों में अक्सर ऐसा किया जाता है। लेकिन नॉन-स्टिक पैन को बिना किसी तेल के तेज़ आंच पर रखने पर अस्वास्थ्यकर धुआं निकलता है। ऐसे में पैन की नॉन-स्टिक कोटिंग को भी

नुकसान पहुंचता है। इसलिए, हमेशा आप हमेशा पैन को हीट पर रखते समय थोड़ा पानी या ऑयल का इस्तेमाल जरूर करें।

हाई हीट को करें अवॉयड

जब भी आप नॉन-स्टिक पैन में खाना बनाते हैं तो हमशा मीडियम या लो तापमान पर ही खाना बनाएं। हाई हीट नॉन-स्टिक कोटिंग को नुकसान पहुंचा सकती है और कुछ कोटिंग से हानिकारक धुआं निकल सकता है। कम तापमान पर खाना पकाने से यह सुनिश्चित होता है कि नॉन-स्टिक कोटिंग उपयोग के लिए सुरक्षित रहे। साथ ही साथ, खाना बिना चिपके प्रभावी ढंग से पकता रहे।

कुकिंग स्प्रे को करें अवॉयड

नॉन-स्टिक कुकवेयर पर एरोसोल कुकिंग स्प्रे आदि का इस्तेमाल ना करने की सलाह दी जाती है। ये स्प्रे एक ऐसा अवशेष छोड़ सकते हैं जिसे हटाना मुश्किल होता है और जो समय के साथ जमा होता जाता है। इससे नॉन-स्टिक कोटिंग की प्रभावशीलता कम हो सकती है।

बर्तनों का सोच-समझकर करें इस्तेमाल

नॉन-स्टिक कुकवेयर से खाना बनाते समय लकड़ी, सिलिकॉन या प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल करना अच्छा माना जाता है। आप मेटल के स्पैटुला, कांटे या चाकू से बचें जो नॉन-स्टिक सरफेस को खरोंच सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस तरह के बर्तन से नॉन-स्टिक कोटिंग छिल सकती है।

'बात खुलेगी तो दूर तक जाएगी', श्रद्धा कपूर को Stree 2 की सफलता का क्रेडिट मिलना 'बिट्टू' को नहीं आया रास ?

नई दिल्ली। स्त्री 2 इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर शेर की तरह दहाड़ रही है। 15 अगस्त पर रिलीज हुई श्रद्धा कपूर-राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी और अपारशक्ति खुराना स्टारर इस फिल्म को ऑडियंस का भरपूर प्यार मिल रहा है। सभी स्टार्स अपने-अपने पुराने किरदार में जान फूंकते हुए नजर आए।

मूवी में जहां विक्की बनकर राजकुमार राव ने अपने मोनोलॉग से एक बार फिर दिल जीता, वहीं पंकज त्रिपाठी के डायलॉग बोलने के अंदाज से थिएटर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हालांकि, फिल्म की सफलता का पूरा क्रेडिट 'स्त्री' यानी कि श्रद्धा कपूर को मिल रहा है, जिनका फिल्म में स्क्रीन टाइम काफी लिमिटेड है। अब हाल ही में अमर कौशिक की फिल्म में 'बिट्टू' का किरदार निभाने वाले अपारशक्ति खुराना ने फिल्म क्रेडिट को लेकर बात की है और साथ ही बातों ही बातों में तंज भी कसा है।

श्रद्धा कपूर को क्रेडिट मिलना नहीं आया अपार को पसंद ?

हाल ही में जूम टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में अपारशक्ति खुराना से जब श्रद्धा कपूर को फिल्म की सफलता के लिए मिल रहे क्रेडिट के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने तपाक से जवाब देते हुए कहा,

₹मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि बात खुलेगी तो दूर तक जाएगी। मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, ऑडियंस जो कहे वो सही है₹।

हालांकि, बातों ही बातों में अपारशक्ति खुराना ने ये तंज भी कसा कि कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस करती है, तो पीआर गेम शुरू हो जाता है, जिसमें आप किसी को ऊपर उठाते हो और किसी को नीचा दिखाते हो। उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजें एक्टर को स्टार बना देती हैं और अन्य स्टारकास्ट को वह अटेंशन नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए।

स्त्री 3 का अब ऑडियंस को है बेसब्री से इंतजार

स्त्री 2 की सफलता के बाद अब हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की सबसे सफल फिल्म 'स्त्री 3' का ऑडियंस को बेसब्री से इंतजार है। कुछ दिनों पहले अपारशक्ति खुराना और अभिषेक बनर्जी ने एक खास बातचीत में बताया था कि फिल्म की स्क्रिप्ट लगभग पूरी हो चुकी है और उसका फ्रेम वर्क भी हो चुका है।

उम्मीद लगाई जा रही है कि 'स्त्री 3' साल 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है। आपको बता दें कि स्त्री 3 में अक्षय कुमार भी नजर आने वाले हैं। स्त्री 2 में उनके कैमियो को देखने के बाद थर्ड पार्ट में खिलाड़ी कुमार को देखने के लिए फैंस एक्साइटेड हैं।

मुंबई के इस अनोखे गांव की सुंदरता देखने के लिए आते हैं विदेशी, खूबरसूरती देखकर दंग रह जाएंगे आप, बनाएं घूमने का प्लान

परिवहन विशेष न्यूज

मुंबई के इस गांव की सुंदरता देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। इस गांव में बने घर इतने खास है कि विदेशी लोग भी यहां का नजारा देखने आते हैं। इस गांव का नाम खोताचीवाड़ी है। यह काफी सुंदर गांव है। मुंबई में स्थित यह गांव रंग बिरंगी घरों से भरा है।

नई दिल्ली। भारत में कई सारे गांव हैं तभी इसे गांव का देश भी कहा जाता है। शहर से कई ज्यादा खूबसूरत गांव होते हैं। गांव की सुंदरता देखकर लोग हैरान भी हो जाते हैं। एक ऐसा ही गांव हमारे बीच में है। यह गांव काफी अनोखा और अद्भुद है। मुंबई के इस गांव की सुंदरता देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। इस गांव में बने घर इतने खास है कि विदेशी लोग भी यहां का नजारा देखने आते हैं। इस गांव का नाम खोताचीवाड़ी है।

मुंबई का खोताचीवाड़ी गांव

मालाबार हिल्स की तलहटी में बसा गिरगांव मूल रुप से एक मछली पकड़ने वाला गांव था। जहां

पहले कोली और पठारे प्रभु सुमदाय के लोग रहते थे। ये बॉम्बे के मूल निवासी थे। खोताचीवाड़ी का नाम इस तथ्य से पड़ा कि इसका मालिक वामन हरि 'खोत' थे। जिसने बाद में जमीन को विभाजित किया और पूर्वी भारतीय ईसाई समुदाय के विभिन्न सदस्यों को अलग-अलग हिस्से बेच दिए।

पुर्तगाली स्टाइल के घर बनें हैं

बता दें कि, इस गांव में आमतौर पर पुर्तगाली शैली की वास्तुकला के रुप में घर बने हुए है। इस गांव में हर घर रंग बिरंगे हैं। इन घरों की बनावट अलग अंदाज में की गई है। एक समय में यहां 65 घर हुआ करते थे, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर 28 रह गई है। दरअसल, नई गगनचुंबी इमारतो के लिए पुरानी इमारतों को गिराया जा रहा है। इस गांव को देखकर पुर्तगाल जैसे देश के माहौल की याद दिलाता है। यहां पर हर रोज कई विदेशी घूमने आते हैं और यहां पर विदेशी पर्यटक के घरों के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाते है।

भारत देश में अजब-गजब गांव

आपको बता दें , केवल खोताचीवाड़ी गांव ही नहीं। भारत में और भी कई सारे अनोखी गांव हैं। जैसे कुलधरा गांव जिसे भूतिया गांव कहा जाता है। देहरादून के सहसपुर ब्लॉक में भी मक्के वाला गांव मौजूद है।

कलर हेयर को नरिश्ड करेंगे ये होममेड मास्क

नारियल का दूध और एलोवेरा कलर बालों में नमी और इलास्टिसिटी को बहाल करने में मदद करता है। नारियल का तेल बालों के शाफ्ट में प्रवेश करता है, जबकि एलोवेरा स्कैल्प को आराम देता है और बालों की ग्रोथ को बेहतर बनाता है।

बालों को कलर करवाना आज के समय में बेहद आम हो गया है। कई बार लोग अपने लुक को थोड़ा ट्रेंडी बनवाना चाहते हैं तो कभी वे अपने सफेद बालों को छिपाने के लिए ऐसा करते हैं। यकीनन बालों को कलर करवाने के बाद आपका ओवर ऑल लुक चेंज हो जाता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कलर में मौजूद केमिकल आपके बालों को डैमेज करता है, जिससे बालों के रूखेपन, उनका बेजान होना व अन्य कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए, बालों को डीप कंडीशनिंग करने की जरूरत होती है। बालों की डीप कंडीशनिंग के लिए आप घर पर ही कुछ हेयर मास्क बनाकर लगा सकते हैं। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे ही हेयर मास्क के बारे में बता रहे हैं, जो आपके कलर हेयर को नरिश्ड करने और उन्हें सिल्की व स्मूथ बनाए रखने में मदद करेंगे-

नारियल का दूध और एलोवेरा हेयर मास्क

नारियल का दूध और एलोवेरा कलर बालों में नमी और इलास्टिसिटी को बहाल करने में मदद करता है। नारियल का तेल बालों के शाफ्ट में प्रवेश करता है, जबकि एलोवेरा स्कैल्प को आराम देता है और बालों की ग्रोथ को बेहतर बनाता है।

आवश्यक सामग्री-

- 1/2 कप नारियल का दूध - 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल - 1 बड़ा चम्मच नारियल का तेल

हेयर मास्क बनाने का तरीका-

- सबसे पहले एक कटोरी में नारियल का दूध, एलोवेरा जेल और नारियल का तेल मिलाएं।
- इस मिश्रण को अपने बालों पर लगाएं, सिरों पर ध्यान दें।
- अपने बालों को शॉवर कैप से ढक लें और मास्क को 1 घंटे तक लगा रहने दें।
- अंत में, ठंडे पानी और सल्फेट-फ्री शैम्पू से धो लें।

अंडा और मेयोनीज हेयर मास्क

अंडे प्रोटीन से भरपूर होते हैं जो डैमेज्ड बालों को मजबूत बनाने और उन्हें रिपेयर करने में मदद करता है। मेयोनेज़ नमी और शाइन जोड़ता है, जिससे यह कलर बालों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। जैतून का तेल बालों को और पोषण देता है और उन्हें मुलायम बनाता है, जिससे वे चमकदार और स्वस्थ दिखते हैं।

आवश्यक सामग्री-

- 1 अंडा - 2 बड़े चम्मच मेयोनीज - 1 बड़ा चम्मच जैतून का तेल

आप में मची भगदड , 5 पार्षद बीजेपी में शामिल

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

दिल्ली विधान सभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बडा झटका लगा है। आप के 5 पार्षदो ने झाड़ू को झटक कर कमल को थाम लिया है। रविवार को आम आदमी पार्टी के 5 निगम पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। जिन 5 पार्षदो ने बीजेपी का कमल थामा है उनमें राम चन्द्र ,बवाना,पवन सहरावत, बवाना,मंजू निर्मल, सुगंधा विधूडी और ममता पवन शामिल है। पाला बदलने वाले पार्षदों में वार्ड-28 से पवन सहरावत,वार्ड-30 ,से मंजू निर्मल, वार्ड-180 से सुगंधा विधुडी,वार्ड-178 से ममता पवन और वार्ड177 के पार्षद है। पांचो आम आदमी पार्टी के पार्षदो के पाला बदलने से बाकी पार्षदो को आप के लिए एकजुट रखने की चुनौती खडी हो गई है। 5 पार्षदो के पार्टी छोडने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता मंत्री सौरभ भारद्वज ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होने कहा कि देश में डर का माहौल है जिसे जाना है वो जाएगा।

उधर आम आदमी पार्टी से नाराज पांचो पार्षदो द्वारा बीजेपी में शामिल होने का कारण बताते हुए कहा आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार और काम न करने के रवैये से तंग आ चुके थे। इनकी एक राय है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी सबको साथ लेकर चल रहे है,उसी तरह से वे भी दिल्ली में अपने लोगो के लिए ऐसा ही काम करना चाहते है दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप के पांचो पार्षदो के बीजेपी में शामिल होने का स्वागत किया है।

सैकड़ों मुस्लिम सदस्यों ने साहसपूर्ण अंगदान की शपथ लेकर पारंपरिक फ़त्वों को चुनौती दी

सुषमा रानी

नई दिल्ली। 'वर्क' एनजीओ के 37वें स्थापना दिवस पर एक प्रेरक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मानवीय कारणों के प्रति एक साहसिक प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया गया। श्री सत्य साईं ऑडिटोरियम, लोधी रोड, प्रगति विहार, नई दिल्ली में आयोजित इस समारोह में एक अग्रणी पहल पर प्रकाश डाला गया, जिसने अंगदान पर अपने साहसिक रुख के लिए सुर्खियाँ बटोरी हैं, खास कर इसके मुस्लिम सदस्यों की ओर से, भले ही इसके खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन हो।

इस कार्यक्रम में आर्ट ऑफ़ लिविंग, गायत्री परिवार, ब्रह्मकुमारी, भारतीय सर्व धर्म संसद, अर्थ-कीपर्स कनेक्ट, द. कोरिया स्थित एच डब्ल्यू पी एल और एहसास जैसे 36 प्रतिष्ठित संगठनों के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट महानुभावों को उन के मानवता एवं समाज के प्रति महत्वपूर्ष योगदान के लिये सम्मानित किया गया। इन संगठनों ने सामाजिक सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सामुदायिक कल्याण के लिए अमूल्य योगदान दिया है। सम्मानित व्यक्तियों में प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान डॉ. एम. असलम परवेज और लोकप्रिय आरजे नावेद खान जैसी प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल थीं। अन्य उल्लेखनीय उपस्थित लोगों में गोस्वामी सुशील महाराज जी, सुनील पांडे, नेहा राजपूत, अब्दुस्समद और तारिक़ इकरामुल्लाह शामिल थे।

अपने संबोधन में, 'वर्क' संस्था के अध्यक्ष अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक़ ने पूरे वर्ष लगातार भारत के लगभग 200 जिलों और

विदेश के 14 शहरों में करुणा के 125 से अधिक क्षेत्रों में 'वर्क' के समर्पित स्वयंसेवकों की सेवाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 'वर्क' न तो सरकार से किसी अनुदान के लिए आवेदन करता है और न ही आम जनता से चंदे की आपील करता है। स्वयंसेवकों को समाज की सेवा में अपना समय और साथ ही अपना पैसा लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है।

अंगदान के बारे में उन्होंने कुरान और हदीस से यह साबित करने के लिए उद्धरण दिया कि अंगदान इस्लाम के अनुसार एक पवित्र कार्य है।

अपने वक्तव्य में, WORK महिला विंग की अध्यक्ष सुमू तारिक़ ने महिला सशक्तीकरण में WORK के योगदान के बारे में बताया और इस क्षेत्र में संस्था की मुस्लिम महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। सुमू तारिक ने कहा, ₹मुस्लिम महिलाओं द्वारा अंगदान की शपथ मानवीय मूल्यों के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का एक शक्तिशाली प्रमाण है।"

इस वर्ष की पहल का एक विशेष रूप से उल्लेखनीय पहलू एक अभूतपूर्व कदम था। WORK संगठन के 400 से अधिक मुस्लिम सदस्यों के नामें का अनावरण किया गया, जिन्होंने अपने अंगों का दान करने की शपथ ली। यह एक ऐसा क़दम है जो ऐसे अनेक मुफ़तियों की आलोचना को आकर्षित कर सकता है जो इस तरह की पहल के खिलाफ फ़तवे जारी कर सकते हैं। WORK संगठन के सदस्यों का यह साहसी रुख मानवीय मूल्यों के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता और राष्ट्रीय हितों में योगदान देने की उनकी इच्छा का प्रमाण है।

WORK NGO करुणा की एक किरण बनी हुई है। इस 37वें स्थापना दिवस पर न केवल पिछली उपलब्धियों का जश्न मनाया गया, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ाने और वंचित समुदायों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से भविष्य के प्रयासों का मार्ग भी प्रशस्त किया गया। WORK NGO और इसकी गतिविधियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया [वेबसाइट] पर जाएँ या [मीडिया संपर्क जानकारी] से संपर्क करें।

देश में 42 जगहों पर पुरातात्विक उत्खनन से मिलेगा इतिहास का पता, ASI ने इस साल पूरे करने के बनाए प्लान

सुषमा रानी

इस साल देश में 42 जगहों पर पुरातात्विक उत्खनन होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने इसके लिए अनुमति दे दी है। इनमें से 17 जगहों पर एएसआई खुद खुदाई कराएगा जबकि 12 जगहों पर विश्वविद्यालयों और 13 जगहों पर राज्यों को खुदाई की अनुमति दी गई है। एएसआई द्वारा दिल्ली हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार महाराष्ट्र असम कर्नाटक व पश्चिम बंगाल में खोदाई किया जाना है।

नई दिल्ली। इस साल देश में 42 स्थानों पर पुरातन इतिहास ढूंढा जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने इसके लिए अनुमति दे दी है। इसमें 17 स्थानों पर एएसआई स्वयं खोदाई कराएगा, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, असम, कर्नाटक व पश्चिम बंगाल शामिल है।

वहीं 12 स्थानों पर विश्वविद्यालयों और 13 स्थानों पर खोदाई के लिए राज्यों को अनुमति दी गई है। एएसआई महत्वपूर्ण स्थानों में हरियाणा के राखी गढ़ी, दिल्ली के पुराना किला और उत्तर प्रदेश के बागपत में तिलवारा और झांसी में राठ तथा बिहार के तेजपुर देउर में खोदाई कराएगा।

हरियाणा के राखीगढ़ी के लिए इस बार फिर अनुमति

एएसआई जमीन में दबे इतिहास से जुड़े साक्ष्यों को खोजने के लिए प्रति वर्ष देश के विभिन्न स्थानों पर खोदाई कराता है। हरियाणा के राखीगढ़ी के लिए इस बार फिर अनुमति दी गई है। यह हड़प्पा से संबंधित सबसे बडे.खोदाई स्थलों में से एक है। यहां पिछले कई बार खोदाई हुई है। यह वह महत्वपूर्ण खोदाई स्थल है जहां से यह सिद्ध हुआ है कि आर्य बाहर से नहीं आए थे बल्कि यहीं के निवासी थे।

चराईदेव स्थित मोइदम के आसपास भी खोदाई

महाभारत काल से संबंधित खोदाई स्थल के रूप में उभरे बागपत के सिनौली से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तिलवारा साकिन के लिए भी इस बार अनुमति दी गई है। यहां एएसआई को पुरातन इतिहास से संबंधित साक्ष्य मिलने की उम्मीद है। इसी तरह असम के चराईदेव स्थित मोइदम के आसपास भी इस बार खोदाई होगी। इसे इसी साल विश्व धरोहर घोषित किया गया है।

चंपारण के बुद्धा स्तूप के आसपास होगी खोदाई

बिहार में चंपारण के बुद्धा स्तूप के आसपास भी एएसआई इस बार खोदाई कर कराने जा रहा है। वहीं दिल्ली के पुराना किला में इस बार भी पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ से संबंधित साक्ष्य ढूंढने के लिए खोदाई की होगी।इसी खोज के लिए आजादी के बाद यहां छठी बार खोदाई होगी।

इसके अलावा राज्यों के पुरातत्व विभाग और देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों को भी एएसआइ द्वारा अनुमति दी गई है।राज्यों की श्रेणी में इस वर्ष तमिलनाडु में सबसे अधिक आठ स्थानों पर खोदाई की अनुमति दी गई है।

जिन 17 स्थानों पर एएसआई कराएगा खोदाई

दिल्ली का पुराना किला
हरियाणा का राखी गढ़ी
उत्तर प्रदेश के तिलवाड़ा साकिन
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर का कछवा
बिहार के चंपारण के तेजपुर देउर का बुद्धा स्तूप
जम्मू कश्मीर के बड़गांव का करटी-वदरे
असम का कल्टीचेरा
असम के चराईदेव का ग्रुप आफ फोर्ट मोइदम
मध्य प्रदेश के पन्ना का नचना कुठेरा
महाराष्ट्र के वर्धा का स्टोन सर्कल
वेलागति का कमलेश्वर मंदिर समूह
तमिलनाडु का अमूर आइरन एज बरियल साइट
कर्नाटक का ब्रहमागिरी
केरल के त्रिचूर का रिजर्ववायर एरिया
पश्चिम बंगाल के कोडूंबलूर के हैबिटेशन माउंड
पश्चिम बंगाल के बीरभूमि का भडीश्वर
गुजरात का लोथल
राज्यों द्वारा कराई जाने वाले खोदाई के प्रमुख स्थल
तमिलनाडु के आठ, आसाम का एक, तेलंगाना व महाराष्ट्र के दो-दो स्थल शामिल हैं।

राजधानी में मौत के गड्ढे: जलभराव में होते हैं हादसे, रात में भी लोग सुरक्षित नहीं

सुषमा रानी

राजधानी दिल्ली में लोग सड़कों पर चलते समय सुरक्षित नहीं हैं। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में सड़कों में मौत के गड्ढे बने हुए हैं। वहीं बारिश में जलभराव के दौरान ये गड्ढे दिखते नहीं है जिस वजह से लोग हादसों के शिकार होते हैं। वहीं रात में भी लोग सड़कों पर चलने असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली में मध्य जिले के अधिकतर इलाकों की सड़कों पर गहरे गड्ढे सड़क हादसों को दावत दे रहे हैं। दरियागंज, दिल्ली गेट, चावड़ी बाजार जैसे व्यस्ततम इलाकों की सड़कों पर गहरे गड्ढों ने लोगों की परेशानी को बढ़ा रखा है। वर्षा के दौरान जलभराव होने से ये गड्ढे और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं और खासकर दो पहिया वाहन सवार घायल हो जाते हैं।

इन सड़कों से प्रतिदिन अधिकारियों का भी गुजरना होता है फिर भी उनकी नजर इन जानलेवा गड्ढों की तरफ नहीं पड़ती है या सब कुछ देखने के बावजूद जिम्मेदार अनजान बने बैठे हुए हैं और किसी बड़ी घटना का इंतिजार कर रहे हैं। कई जगह तो हालात इतने बदतर हैं

कि रात के समय लोग इन सड़कों से गुजरने से भी डरते हैं।

नगर निगम मुख्यालय के बाहर ही गहरा गड्ढा बना आफत

नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां वह बैठते हैं उसके बाहर ही जानलेवा गड्ढा बना हुआ है। नगर निगम के अधिकारियों की गाड़ियां प्रतिदिन इस गड्ढे से हिचकौला खाती है उसके बाद भी इसकी मरम्मत के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। दिल्ली नगर निगम मुख्यालय के बाहर ही जब गड्ढे को ठीक नहीं कराया जा रहा है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाकी सड़कों की स्थिति किस हालत में होंगी।

आसफ अली रोड पर गड्ढे बेशुमार

मध्य जिले के सबसे व्यवस्ततम रोड में से एक आसफ अली रोड पर गड्ढे किसी बड़े हादसे को न्यौता दे रहे हैं। यहां प्रसिद्ध डिलाइट सिनेमा हाल के बाहर सड़क की हालत इतनी भयावह है कि यहां अकसर बाइक सवार व पैदल चलने वाले राहगीर गड्ढों में आने चोटिल होते हैं। इस सड़क पर पिछले एक महीने में करीब दस से बारह लोग घायल हो चुके हैं। उसके बाद भी जिम्मेदारों की नींद नहीं खुल रही है।

मिंटो रोड की सड़कों की हालत खस्ताहाल

नई दिल्ली जिले के मिंटो रोड इलाके की सड़कें भी खस्ताहाल में हैं। यहां की प्रसिद्ध गांधी मार्केट में बीच सड़क पर गहरा गड्ढा मौत को दावत दे रहा है। बीचों बीच गहरे गड्ढे से स्थानीय निवासी गुजरने से डर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई बार समस्या को लेकर अधिकारियों को अवगत करा दिया है बावजूद इसके सड़कों की मरम्मत को लेकर कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है।

इसके अलावा दरिया गंज के अंसारी रोड पर भी सड़कों की हालत बदतर स्थिति में है। यहां स्थित संजीवन अस्पताल के बाहर करीब सौ मीटर तक सड़क पर गहरे गड्ढे देखने को मिलते हैं। जिससे राहगीरों को वर्षा के दौरान परेशानी झेलनी पड़ती है। जलभराव की स्थिति में तो समस्या और भी भयावह हो जाती है।

सड़क पर हो रहे गड्ढों के बारे में जानकारी संज्ञान में आई है। लोगों की परेशानी को देखते हुए जल्द ही सड़कों पर जगह-जगह हो रहे गड्ढों की मरम्मत करवाई जाएगी। - आले मोहम्मद इकबाल, डिप्टी मेयर, नगर निगम

हरियाणा में चुनाव तारीख में हो सकता है बदलाव ?

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख में हो सकता है बदलाव। सूत्रो के मुताबिक 1 अक्टूबर की जगह मतदान अब 7-8 अक्टूबर को हो सकता है। सूत्रो के मुताबिक चुनाव आयोग इस बावत मंगलवार को फैसला ले सकता है। परिणाम की तारीख को भी 4 अक्टूबर की जगह आगे बढाया जा सकता है। बता दें कि बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक दलों की गुहार पर चुनाव आयोग इस बावत मंगलवार को फैसला ले सकता है। उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग ने हरियाणा में एक चरण में चुनाव के तहत मतदान की तारीख 1 अक्टूबर की मुकर्रर की हुई है। और चुनाव परिणाम 4 अक्टूबर को घोषित कर देने की बात थी। अगर तमाम दलों की गुहार पर चुनाव तारीख में बदलाव होता है तो मंगलवार.को फैसला सामने आ सकता है। वहीं चुनाव परिणाम की तारीख 4 अक्टूबर से बढाकर आगे की तय की जा सकती है।

लालबाग का राजा दिल्ली गणपति महोत्सव का हुआ भूमि पूजन

सुषमा रानी

भगवान गणेश देव शुभकर्ता, विघ्नहर्ता लाल बाग का राजा दिल्ली ट्रस्ट (पंजी) द्वारा गणपति महोत्सव का भूमि पूजन किया गया जो 7 सितंबर से 16 सितंबर तक होने जा रहा है। संस्था के चेयरमैन राकेश बिंदल ने बताया कि लाल बाग का राजा ट्रस्ट (पंजी) दिल्ली द्वारा आयोजित गणपति महोत्सव दिल्ली में होने वाला सबसे बड़ा गणेश महोत्सव है भूमि पूजन के अवसर पर लाल बाग का राजा ट्रस्ट के नव निर्वाचित प्रधान प्रदीप कुमार अग्रवाला सहपत्नी उपस्थित हुए व हवन व पूजा मैं भाग लिया । राकेश जी ने आगे बताया कि यहां 1 लाख से 2 लाख तक श्रद्धालु दर्शन के लिए आ सकते है, यहाँ विभिन्न प्रदेश व प्रांतों के कई प्रकार के पकवान व प्रसिद्ध चाट पापड़ी के स्टॉल की व्यवस्था की जाएगी साथ ही आधुनिक व क्लासिकल झूलो का भी इंतज़ाम किया जाएगा ताकि बच्चे व बड़े आनंद ले सकें। इस बार 5 दिन बाबा बागेश्वर जी व 5 दिन अनिरुद्धाचार्य महाराज के दिव्य प्रवचन व भजन भी सुनने को मिलेंगे। वाइस चेयरमैन सत्यभूषण जैन ने कहा इस बार कई केंद्रीय मंत्री जैस मनोज तिवारी व प्रवीन खंडेलवाल वा अन्य मंत्री के आने की संभावना है हमारी पूरी तैयारी है इस आयोजन को सफल बनाने की, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का भी पुख्ता इंतजाम किया जाएगा व जगह जगह पर डस्टबिन भी रखे जाएंगे ताकि लोग स्वच्छता का ध्यान रखें। राकेश बिंदल ने बताया कि इस बार स्टेज 200X600 फुट का लगाया जाएगा जिसमें 100X200 फीट का गुरु का स्टेज रहेगा। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष त्यागी व कोषाध्यक्ष कुशल गुप्ता और सुभाष चंद गुप्ता उपस्थित रहे।

दिल्ली-एनसीआर में 26 और 27 अगस्त के लिए येलो अलर्ट जारी, आज भी बरसेंगे बादल

दिल्ली एनसीआर में 26 और 27 अगस्त के लिए येलो अलर्ट किया गया है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार आज यानी रविवार की शाम को भी बारिश के आसार हैं। सुबह कई इलाकों में बारिश हुई थी लेकिन गर्मी से फिर भी लोगों को राहत नहीं मिली है। पढ़िए सुबह कहां-कहां पर बारिश हुई थी?

नईदिल्ली। राजधानी दिल्ली में बीती रात व आज रविवार सुबह कुछ इलाकों में हल्की वर्षा हुई। फिर भी उमस भरी गर्मी बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार, देर शाम तक दिल्ली के कई इलाकों में हल्की वर्षा हो सकती है।

वहीं, मौसम विभाग ने मंगलवार व बुधवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस वजह से अगले सप्ताह दो दिन हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है।

कहां कितनी हुई बारिश : मौसम विभाग के अनुसार, आया नगर में मध्यम रात्रि के बाद 17.2 मिलीमीटर वर्षा हुई। रिज एरिया में नौ मिलीमीटर व सफदरजंग में 0.6 मिलीमीटर वर्षा हुई। रात ढाई से सुबह साढ़े पांच बजे के बीच दिल्ली विश्वविद्यालय में 8.5 मिलीमीटर, पीतमपुरा में छह मिलीमीटर, नरेला व मयूर विहार में ढाई मिलीमीटर, पूसा में सुबह एक मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।

और भी कई इलाकों में हुई वर्षा : इसके अलावा भी कुछ इलाकों में हल्की वर्षा हुई। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

एयर इंडेक्स में हुआ है सुधार : उधर, बीती रात व सुबह में कुछ इलाकों में वर्षा होने के कारण एयर इंडेक्स में सुधार हुआ है। इस वजह से दिल्ली में सुबह के वक्त एयर इंडेक्स 100 से कम होने के कारण हवा की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में रही। शनिवार को दिल्ली में हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में थी।

क्या है कांग्रेस का प्लान?: ये हॉट सीट गंवाना नहीं चाहती पार्टी, समझिए पूरा गणित; 2019 में BJP ने मारी थी बाजी

परिवहन विशेष न्यूज

आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तरह इन चुनावों में भी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने हरियाणा की इस टॉट सीट के लिए प्लान बनाना शुरू कर दिया है। इस सीट पर पिछले चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी थी। पढ़िए आखिर कौन सी सीट है?

गुरुग्राम। हॉट सीट मानी जाने वाली गुड़गांव विधानसभा सीट से 15 साल का सूखा खत्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी Congress Party पूरी तरह से कसी रणनीति बना रही है। पार्टी हाईकमान ऐसे उम्मीदवार की तलाश कर रहा है, जिसकी मतदाताओं के बीच अच्छी पैठ हो। यहां से जिताऊ प्रत्याशी को टिकट देने के लिए गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र के जातीय समीकरण को भी देखा जा रहा है।

खबीर कटारिया ने 2009 में जीता चुनाव

गुड़गांव विधानसभा सीट पंजाबी बाहुल मानी जाती है। हालांकि, विधानसभा क्षेत्र बनने के बाद 1967 से 2019 तक अब तक हुए 13 बार विधानसभा चुनावों में चार बार जाट, चार बार पंजाबी, तीन बार बनिया और दो बार यादव बिरादरी से विधायक जीत कर आए। पंजाबी समाज से अकेले धर्मबीर गाबा ही चार बार 1982, 1991, 1996 और 2005 में विधायक बने। जबकि जाट समुदाय से आने वाले प्रताप सिंह ठाकरान दो बार 1967 व 1977, गोपीचंद गहलोत 2000 और सुखबीर कटारिया ने 2009 में चुनाव जीता।

महाबीर सिंह यादव ने दो बार परचम लहराया

इसके अलावा बनिया बिरादरी से आने वाले सीताराम सिंगला ने 1987, उनके बेटे सुधीर सिंगला ने 2019 और उमेश अग्रवाल ने 2014 में चुनाव अपने नाम किया। इस सीट से दो बार महाबीर सिंह यादव ने परचम लहराया। इसके अलावा इस सीट से अन्य किसी भी जाति के नेता ने चुनाव नहीं जीता।

बता दें कि विधानसभा क्षेत्र में इस समय 4,30,893 वोटर हैं। इनमें सबसे ज्यादा पंजाबी, फिर बनिया, ब्राह्मण, यादव और जाट समाज के वोटर हैं। कांग्रेस पार्टी इन सभी समीकरणों को भी देख रही है।

वहीं, इस बार इस सीट से 32 कांग्रेस नेताओं ने टिकट के लिए आवेदन किया है। इसमें भी सबसे ज्यादा जाट, पंजाबी, ब्राह्मण और बनिया समाज से आने वलो नेताओं ने दावेदारी की है। पार्टी इन्हीं दावेदारों में से किसी एक पर दांव खेल सकती है।

इन्होंने किया आवेदन

पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव आशीष दुआ, पंकज डावर, मोहित ग्रोवर, विपिन खन्ना, कुलराज कटारिया, गजे सिंह कबलाना, राहुल यादव, सुनीता सेहरावत, ओम प्रकाश अखेरिया धोबी, प्रो. सुभाष सपरा, विजेंद्र कुमार जिंदल, धर्मेंद्र ठाकरान, कुलदीप कटारिया, सीमा गुप्ता आजाद, सुभाष चंद, मुकेश शर्मा, अरुण कुमार शर्मा, नवीन शर्मा, रश्मि शर्मा, विजय शर्मा, खुशबू शर्मा मंगला, सिया शर्मा, निर्मल यादव, करन कटारिया, राम किशन सेन, कन्हैया लाल पहवा, इंदर सिंह सैनी, सूबे सिंह यादव, हरकेश वाल्मीकि, सुनील, मंदीप सेहरा

विधानसभा क्षेत्र गुड़गांव (Haryana Election 2024)

मतदाताओं की संख्या : 4,30,893
पुरुष मतदाता : 2,25,537
महिला मतदाता : 2,05,335
थर्ड जेंडर : 21

हज यात्रियों के लिए नई नियमावली: पंजीकरण शुल्क समाप्त, सुविधा शुल्क हुआ दोगुना

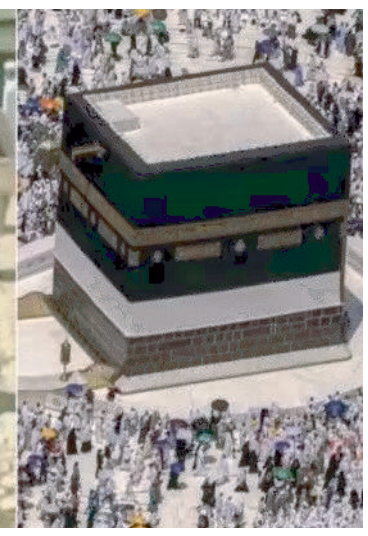

हज यात्रियों के लिए नई नियमावली जारी इस बार पंजीकरण शुल्क समाप्त कर दिया गया है लेकिन सुविधा शुल्क दोगुना कर दिया गया है। 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के जायरीन अब अकेले नहीं जा सकेंगे। यात्रा के दौरान अब पति-पत्नी एक कमरे में नहीं रह सकेंगे। हज यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 सितंबर तक मांगे गए हैं।

गाजियाबाद। हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से इस बार हज यात्रियों के लिए नई नियमावली के साथ गाइडलाइन जारी की गई है। इस बार सरकार ने जहां पंजीकरण शुल्क समाप्त किया है, वहीं सुविधा शुल्क को दोगुना कर दिया है। इस बार 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के जायरीनों के अकेले जाने पर पाबंदी होगी। पहले यह आयु सीमा 70 वर्ष थी।

हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से हज यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन नौ सितंबर तक मांगे गए हैं। सरकार ने हज यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए लगने वाले 300 रुपये के पंजीकरण शुल्क को खत्म करते हुए सुविधा शुल्क एक हजार की जगह दो हजार रुपये कर दिया है। यात्रा के दौरान अब पति-पत्नी एक कमरे में नहीं रह सकेंगे। यह फैसला हज कमेटी ऑफ इंडिया का नहीं बल्कि सऊदी अरब सरकार ने लिया है।

यात्रियों को एक बिल्डिंग में ठहराया जाएगा

सऊदी सरकार के मुताबिक पुरुष, महिला के कमरे में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। अभी तक हज कमेटी ऑफ इंडिया राज्यवार महिला-पुरुष का ग्रुप बनाकर एक कमरे में ठहराने की व्यवस्था करती रही है। कमेटी की ओर से इस बार जिलेवार हज यात्रियों को एक बिल्डिंग में ठहराया जाएगा। पति-पत्नी के कमरे अगल-बगल रहेंगे।

"हज यात्रा पर जाने वाले समय से आवेदन के साथ अपना पासपोर्ट और हज यात्रा की तमाम तैयारी मुकम्मल कर लें। हज कमेटी की ओर से किए गए बदलाव का भी खयाल रखें। - हाजी रहीमुद्दीन, जिला हज ट्रेनर"

'पहले आओ-पहले पाओ' योजना से भरी GDA की झोली, पुरानी स्कीम में धड़ाधड़ बिके फ्लैट

पहले आओ पहले पाओ योजना के तहत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की निष्क्रिय संपत्तियों की बिक्री से प्राधिकरण के वारे-न्यारे हो गए हैं। मधुबन बापूधाम ई पॉकेट के सभी भवन और चंद्रशिला अपार्टमेंट के अधिकांश फ्लैट बिक चुके हैं। इस योजना से प्राधिकरण की झोली में करोड़ों रुपये आए हैं। लोगों की सुविधा के लिए मौके पर शिविर लगाया जाएगा।

गाजियाबाद। जीडीए की पिछले कई वर्षों से खरीदारों की बाट जोह रहीं कई निष्क्रिय संपत्तियों की पहले आओ पहले पाओ योजना के तहत धड़ाधड़ बिक्री हुई है। इसमे खरीदारों ने मधुबन बापूधाम के ई पाकेट के सभी भवनों की खरीद करने के साथ ही शहर के बीच चंद्रशिला अपार्टमेंट के अधिकांश फ्लैट को खरीद लिया है।

जीडीए ने 15 अगस्त से शुरू की योजना

पहले आओ पहले पाओ योजना से खरीदारों के साथ प्राधिकरण के लिए आय के साधन खुले हैं। कई-कई वर्षों से निष्क्रिय संपत्ति को खरीदार मिले हैं। इस योजना को जीडीए ने स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त से आरंभ किया। इसमें मधुबन बापूधाम ई पॉकेट में जहां शत प्रतिशत फ्लैट की बिक्री हो गई।

चंद्रशिला अपार्टमेंट योजना में 22 फ्लैट बिके

वहीं, चंद्रशिला अपार्टमेंट योजना के 28 में 22 फ्लैट की बिक्री हुई। संजयपुरी मोदीनगर योजना में भी खरीदारों ने दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि अभी मधुबन बापूधाम के एफ और सी पॉकेट में उम्मीद से कम खरीदार संपत्ति खरीदने के लिए आगे आए हैं। योजना के तहत कुल 1095 संपत्तियों में 78 की बिक्री हुई है, जिससे प्राधिकरण को 19,41,42000 की आय हुई है।

गुरुग्राम में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, दो फ्लैट से चल रहा था ठगी का धंधा; चार महिलाओं समेत 20 गिरफ्तार

परिवहन विशेष न्यूज

सोहना में दो फ्लैट से फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया गया है। आरोपित भारत के आठ राज्यों गुजरात बंगाल मणिपुर नागालैंड मिजोरम जम्मू-कश्मीर उत्तर प्रदेश दिल्ली और पड़ोसी देश नेपाल के रहने वाले हैं। तकनीकी सहायता देने के नाम पर दूसरे देश के नागरिकों को ठगी का शिकार बनाते थे। आरोपितों में चार महिलाएं भी शामिल हैं। इनके पास से लैपटाप और मोबाइल बरामद किए गए हैं।

गुरुग्राम। साइबर पुलिस ने शनिवार को सोहना की फ्लोरा एवेन्यू सोसायटी के दो फ्लैट में छापेमारी कर फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। यहां से चार महिलाओं समेत 20 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग दूसरे देश के नागरिकों को टेक्निकल सपोर्ट की कस्टमर केयर सर्विस प्रदान करने के नाम पर ठगी करते थे।

एसीपी साइबर प्रियांशु दीवान ने बताया कि जिले में साइबर ठगों के विरुद्ध आपरेशन इंडगेम चलाया जा रहा है। मुखबिर से सूचना मिलने पर साइबर दक्षिण थाना पुलिस की टीम ने सोहना की फ्लोरा एवेन्यू सोसायटी के फ्लैट नंबर ए-21, 22 छापेमारी की।

धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में केस दर्ज

यहां दोनों फ्लैटों से चार महिलाओं समेत 20 लोगों को पकड़ा गया। ये सभी गुजरात, बंगाल, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पड़ोसी देश नेपाल के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ थाने में धोखाधड़ी व अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया गया।

पूछताछ में पता चला अहमदाबाद निवासी महेंद्र बजरंग सिंह इस कॉल सेंटर का मैनेजर था। यह अपने साथियों व कर्मचारियों के साथ मिलकर मई 2024 से दो फ्लैटों में कॉल सेंटर चला रहा था। यहां से 16 लैपटाप व 25 मोबाइल फोन तथा 50 हजार रुपये की नकदी बरामद की गई।

ऐसे करते थे ठगी

पूछताछ में पता चला कि ये लोग वेंडर के माध्यम से दूसरे देश के नागरिकों के कंप्यूटर में पाप-अप यानी विज्ञापन भेजते थे। इसमें टोल फ्री नंबर होता था। नागरिकों द्वारा टोल फ्री नंबर पर कॉल करने पर वीओआइपी एप के माध्यम से कॉल इनके कॉल सेंटर पर आती थी।

ये लोग खुद को नामी कंपनी का टेक्नीशियन बताते थे। समस्या दूर करने के लिए उनके सिस्टम में अल्ट्रा व्यूवर एप डाउनलोड करवा कर रिमोट एक्सेस प्राप्त कर लेते।

हैकर द्वारा उनका कंप्यूटर हैक करने की बात कहकर व समस्या को दूर करने के नाम पर सौ से पांच डालर तक के गिफ्ट कार्ड ले लेते थे। इसके बाद दूसरे देशों में बैठे अन्य साथियों से गिफ्ट कूपन को क्रिप्टोकरेंसी में ट्रांसफर करवा लेते थे।

मोदी का विजन और विभाजनकारी विचार

पी. चिदम्बरम

यह स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री का लगातार 11वां भाषण था, जो एक तरह से रिकॉर्ड है। यह नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले की प्राचीर से दिया गया सबसे लंबा भाषण (98 मिनट) था। यह उनके तीसरे कार्यकाल की शुरूआत थी और उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री अगले 5 वर्षों के लिए सरकार के लिए अपना विजन पेश करेंगे। भाजपा नेताओं ने भाषण को एक साहसिक नए विजन को सामने लाने वाला बताया। अगर ऐसा था, तो मुझे डर है कि यह एक ऐसा विजन था जो लोगों के एक वर्ग को लक्षित करता था। प्रधानमंत्री ने कहा, हम संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन एक और सच्चाई यह है कि कुछ लोग हैं जो भारत की प्रगति को पचा नहीं सकते।

कुछ लोग भारत के लिए अच्छी चीजों की कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि उनके अपने निहित स्वार्थ पूरे नहीं होते, इसलिए उन्हें किसी की प्रगति पसंद नहीं आती। ऐसी विकृत मानसिकता वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। देश को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए।

लोकतंत्र के प्रति तिरस्कार : 'कुछ लोग' कौन हैं? मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता जो कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष आदि में भारत की प्रगति पर गर्व न करता हो। क्या प्रधानमंत्री उन 262 मिलियन मतदाताओं की ओर इशारा कर रहे थे जिन्होंने उनके और एन.डी.ए. के खिलाफ वोट दिया? या उन युवाओं की ओर जो बढ़ती बेरोजगारी के लिए उनकी आलोचना करते हैं? या उन गृहणियों की ओर जो बढ़ती महंगाई के बोझ की शिकायत करती हैं? या

उन सैनिकों और पूर्व सैनिकों की ओर जो चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र पर बेशर्मी से कब्जा किए जाने के बावजूद भारत के चुपचाप पीछे हटने से हैरान हैं? भारत के लिए एक दृष्टिकोण के इर्द-गिर्द लोगों को एकजुट करने के उद्देश्य से दिए गए भाषण में, प्रधानमंत्री ने वास्तव में अपनी सरकार की गलत नीतियों के कारण लोगों के बीच विभाजन को और बढ़ा दिया। अपनी सरकार के विरोधियों को 'विकृत' कहना लोकतांत्रिक फैसले के प्रति तिरस्कार दर्शाता है। अगर हमने सोचा था कि भाजपा के 240 सीटों पर सिमट जाने के बाद कुछ मुद्दे पीछे छूट जाएंगे, तो हम गलत थे। जाहिर है, प्रधानमंत्री अभी भी समान नागरिक संहिता (यू.सी.सी.) और एक राष्ट्र-एक चुनाव (ओ.एन.ओ.ई.) के विचार की कसम खाते हैं।

उन्होंने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में दोनों का उल्लेख किया। उन्होंने मौजूदा व्यक्तिगत कानून संहिताओं को 'सांप्रदायिक नागरिक संहिता' करार दिया और कहा- आधुनिक समाज में ऐसे कानूनों के लिए कोई जगह नहीं है जो देश को धार्मिक आधार पर विभाजित करते हैं और वर्ग भेदभाव का आधार बनते हैं। मैं कहूंगा, और यह समय की मांग है कि देश में एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता होनी चाहिए। हमने सांप्रदायिक नागरिक संहिता के तहत 75 साल बिताए हैं। अब हमें एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की ओर बढना होगा। तभी हम धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाले कानूनों के कारण होने वाली दरार से राहत पा सकेंगे। यह कथन त्रुटि, खराब समझ और पूर्वाग्रह का मिश्रण था। हर व्यक्तिगत कानून संहिता धर्म पर आधारित है, जिसमें हिंदू संहिता भी शामिल है, लेकिन इससे संहिता सांप्रदायिक नहीं हो जाती। विवाह पर एक धर्मनिरपेक्ष संहिता है, जिसका नाम विशेष विवाह अधिनियम है, लेकिन यह भारत के लोगों के बीच लोकप्रिय नहीं है। आम आदमी (हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख या पारसी) को यह महसूस नहीं होता कि उसके पड़ोसी पर किसी दूसरे कोड का शासन है। यह बहुत बढिया होगा अगर सभी धार्मिक समूह और समुदाय एक समान नागरिक संहिता पर सहमत हो जाएं, लेकिन ऐसा कहना आसान है, करना मुश्किल।

विभाजनकारी बयानबाजी : यू.सी.सी.या ओ.एन.ओ.ई. का विचार ही खतरे की घंटी बजाता है और सबसे पहले डर को दूर करना जरूरी है। मैंने पिछले कॉलम (पंथ पूजा और परिणाम, पंजाब केसरी, 21 अप्रैल, 2024) में यू.सी.सी.और ओ.एन.ओ.ई.के छिपे हुए एजैंडे के बारे में बताया था। यू.सी.सी.के लिए सभी धार्मिक समूहों और समुदायों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करना जरूरी है। ओ.एन.ओ.ई. के लिए संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन करना जरूरी है।

प्रधानमंत्री का भाषण मुद्दों पर बहस की शुरूआत या अंत नहीं है। इसके विपरीत, इसका मतलब यह होगा कि विभाजनकारी मुद्दे उठाए जाएंगे और संसद के माध्यम से कानून पारित किए जाएंगे जो लोगों को और विभाजित कर सकते हैं।

लोकसभा चुनाव में बहुत विभाजनकारी बयानबाजी देखने को मिली। कांग्रेस के घोषणापत्र 2024 पर हमला करते हुए मोदी ने कहा-

- कांग्रेस लोगों की जमीन, सोना और अन्य कीमती सामान मुसलमानों में बांट देगी।

-कांग्रेस आपका मंगलसूत्र और स्त्रीधन छीनकर उन लोगों को दे देगी जिनके अधिक बच्चे हैं।

- अमित शाह ने कहा, 'कांग्रेस मंदिरों की संपत्ति जब्त करके उन्हें बांट देगी।'

-राजनाथ सिंह ने कहा, 'कांग्रेस लोगों की संपत्ति हड़पकर उन्हें घुसपैठियों में बांट देगी।'

चुनाव के नतीजों ने प्रधानमंत्री को नहीं रोका है, लेकिन सत्ता खोने के डर ने उनकी सरकार को कई मुद्दों पर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। पूंजीगत लाभ के लिए इंडैक्सेशन लाभ बहाल कर दिया गया है, वक्फ विधेयक को एक प्रवर समिति को भेज दिया गया है, प्रसारण विधेयक को वापस ले लिया गया है और केंद्र सरकार के पदों पर पाश्र्व प्रवेश की योजना को स्थगित कर दिया गया है। अधिक विभाजनकारी विचारों का डर तभी खत्म होगा जब सी.ए.ए., यू.सी.सी. और ओ.एन.ओ.ई.को अंततः वापस ले लिया जाएगा।

'कई सांसद-विधायक आपराधिक मामलों में संलिप्त' 'लोगों को सुशासन कैसे मिलेगा!'

परिवहन विशेष न्यूज

हालांकि हमारे जन प्रतिनिधि सांसदों, विधायकों से बेदाग छवि के होने की उम्मीद की जाती है परन्तु इसके विपरीत कई माननीय आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जा रहे हैं और उनके विरुद्ध दबंगई, महिलाओं के यौन-शोषण आदि के आरोप लग रहे हैं। ऐसे ही चंद उदाहरण...

हालांकि हमारे जन प्रतिनिधि सांसदों, विधायकों से बेदाग छवि के होने की उम्मीद की जाती है परन्तु इसके विपरीत कई माननीय आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जा रहे हैं और उनके विरुद्ध दबंगई, महिलाओं के यौन-शोषण आदि के आरोप लग रहे हैं। ऐसे ही चंद उदाहरण निम्न में दर्ज हैं :

* 15 दिसम्बर, 2023 को उत्तर प्रदेश में सोनभद्र की 'दुद्धी' विधानसभा सीट से भाजपा विधायक 'राम दुलार गोंड' को सोनभद्र की विशेष अदालत (एम.पी./एम.एल.ए.) ने एक नाबालिगा से बलात्कार करने के आरोप में 25 वर्ष कैद तथा 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

* 29 अप्रैल, 2024 को कर्नाटक में जद (एस.) के सुप्रीमो तथा पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के विधायक बेटे एच.डी. रेवन्ना (67) व सांसद पौत्र प्रज्वल रेवन्ना (33) के विरुद्ध उनकी घरेलू सहायिका ने यौन शोषण और ब्लैकमेल करने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई।

* 22 मई, 2024 को केरल पुलिस की अपराध शाखा ने 'पेरूंबेवूर' के विधायक एवं कांग्रेस नेता 'एल्धोस कुन्नापल्ली' तथा उसके 2 साथियों के विरुद्ध अलग-अलग जगहों पर एक महिला के साथ कई बार बलात्कार करने और फिर झगड़ा हो जाने पर उसकी हत्या करने की कोशिश के आरोप में आरोप पत्र दाखिल किया। राजनीति में प्रभावशाली लोगों तथा जन प्रतिनिधियों द्वारा महिलाओं के उत्पीडन के मात्र यही मामले नहीं हैं। चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाली संस्था 'एसोसिएशन फॉर डैमोक्रेटिक रिफाम्र्स' (ए.डी.आर.) के अनुसार देश में 151 वर्तमान सांसदों और विधायकों ने अपने चुनावी हलफनामों में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से सम्बन्धित मामलों की जानकारी दी है। इनमें पश्चिम बंगाल के सांसदों तथा विधायकों की संख्या सर्वाधिक है।

ए.डी.आर. ने 2019 तथा 2024 के बीच चुनावों के दौरान निर्वाचन आयोग को सौंपे गए वर्तमान सांसदों तथा विधायकों के 4809 हलफनामों में से 4693 हलफनामों की जांच के बाद जारी अपनी रिपोर्ट में महिलाओं से जुड़े अपराधों से सम्बन्धित मामलों का सामना कर रहे 16 सांसदों तथा 135 विधायकों को चिन्हित किया है। रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं से जुड़े अपराध से सम्बन्धित आरोपों का सामना कर रहे 25 सांसदों और विधायकों के साथ पश्चिम बंगाल शीर्ष पर है जबकि इसके बाद आंध्र प्रदेश (21) तथा ओडिशा (17) का स्थान है। राजनीतिक दलों में भाजपा के सर्वाधिक 54 सांसदों और विधायकों पर महिलाओं से जुड़े अपराध के मामले दर्ज हैं। इसके बाद कांग्रेस (23) तथा तेदेपा (17) के सांसद और विधायक हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों के 5-5 वर्तमान सांसद-विधायक बलात्कार के आरोपों का सामना कर रहे हैं।

ए.डी.आर. ने कहा है कि ऐसे हालात में राजनीतिक दलों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को, विशेषकर जिन पर बलात्कार और महिलाओं के विरुद्ध अन्य अपराधों के आरोप हैं, उम्मीदवार बनाने से संकोच करना चाहिए।

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर

दक्षिण कोरिया आग लगने की घटनाओं के बाद ईवी बैटरी प्रमाणन योजना को बढ़ाएगा आगे

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दक्षिण कोरिया की सरकार और पार्टी ने इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी प्रमाणपत्र योजना को आगे बढ़ाया है, पार्टी ने रविवार, 25 अगस्त को कहा, क्योंकि अधिकारी आग से सुरक्षा की घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद ईवी के सार्वजनिक विज्ञापन को कम करना चाहते हैं। पीपुल पावर पार्टी के प्रवक्ता हान ज़िया ने द प्लाज़ा को बताया कि सरकार अक्टूबर में ईवी बैटरियों की सुरक्षा में मदद करने के लिए बैटरी क्रेडिट योजना शुरू करेगी। सरकार ने देश में चलने वाले वाहनों को उनके इलेक्ट्रिक क्लस्टर में इस्तेमाल की गई बैटरियों की पहचान करने की आवश्यकता पर भी सहमति व्यक्त की है।

ईवी सुरक्षा को सख्त करने पर समझौता सरकार द्वारा कार डीन से जानकारी का खुलासा करने का अनुरोध करने के कदम के बाद हुआ है, जो 1 अगस्त को ईवी आग की एक श्रृंखला के बाद हुआ था जिसमें सैकड़ों वाहन नष्ट हो गए थे और लोगों में दहशत फैल गई थी। फ़ारासिस एनर्जी बैटरी वाली मर्सिडीज-बेंज ईवी में स्वतः ही आग लग गई थी, जिसे आठ घंटे तक बेस तक सीमित रखा गया था, जिससे लगभग 140 इकाइयाँ नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गईं और ऊपर के अपार्टमेंट में रहने वाले कुछ निवासियों को आश्रय में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हाल के दिनों में कुछ कार एसोसिएशनों ने उन बैटरियों के निर्माताओं का नाम बताना शुरू कर दिया है जिनका वे उपयोग करते हैं। उद्योग अधिकारियों ने पहले प्रदर्शनकारियों से कहा था कि दक्षिण कोरियाई बैटरी निर्माताओं के पास यह दावा करने का कोई कारण नहीं है कि उनकी ऊर्जा का उपयोग किया गया है, हालांकि लोगों को यह एहसास नहीं था कि ईवी आग के लिए हमेशा बैटरी को दोषी ठहराया जाता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि कार कंपनियों से बैटरी पहचान की जाँच करने से अधिक विकल्प मिलेंगे, लेकिन कुछ लोग इस बात को लेकर संशय में हैं कि इस सुरक्षा को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि बैटरी की पहचान के ब्रांड की तुलना में बैटरी के किस ब्रांड को अधिक जोखिम है, इस पर निश्चित डेटा की कमी है। पार्टी प्रवक्ता हान ने कहा कि सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए सरकार ईवी के लिए अग्नि उपकरणों को संशोधित कर रही है और साथ ही आवासीय प्रतिष्ठानों में गीले पाइप स्प्रेयर सिस्टम लगा रही है और ओवरचार्जिंग को रोकने वाले चार्जर का विस्तार कर रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने का खतरा नहीं हाल की रिपोर्टें कुछ डेटा की ओर इशारा करती हैं जो दिखाती हैं कि ईवी में पारंपरिक कारों की तुलना में आग लगने का खतरा कम होता है।

टाटा मोटर्स ने भारत के ईवी चार्जिंग ग्रिड को बढ़ाने के लिए डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स और थंडरप्लस सॉल्यूशंस के साथ किया समझौता

परिवहन विशेष न्यूज

घरेलू वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने देश भर में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया और थंडरप्लस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ सहयोग की घोषणा की है। इस साझेदारी का उद्देश्य उच्च यातायात मार्गों पर चार्जिंग स्टेशनों की उपलब्धता का विस्तार करके, विशेष रूप से वाणिज्यिक क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना है।

तीनों कंपनियों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) में इस पहल में उनकी संबंधित भूमिकाओं को रेखांकित किया गया है:-

टाटा मोटर्स नए चार्जिंग स्टेशनों के लिए स्थानों की पहचान करेगी और डीलरशिप की सिफारिश करेगी।

डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स आवश्यक चार्जिंग हार्डवेयर की आपूर्ति करेगा।

थंडरप्लस सॉल्यूशंस स्टेशनों की स्थापना और संचालन की देखरेख करेगा।

टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स के उपाध्यक्ष और बिजनेस हेड (एससीवी एवं पीयू) विनय पाठक ने बताया कि इन चार्जिंग पॉइंट्स की उपलब्धता ग्राहकों को इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों को चुनने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

विनय पाठक ने कहा, ₹हमारा प्रयास उत्सर्जन मुक्त कार्गो परिवहन को आसानी से सुलभ बनाना है। उच्च उपयोग वाले मार्गों पर उपलब्ध चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने से अधिक ग्राहक इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों को चुनने के लिए प्रोत्साहित होंगे और वाहन के अपटाइम में सुधार होगा, जिसके परिणामस्वरूप अधिक राजस्व और बेहतर लाभप्रदता होगी, जबकि स्वच्छ, हरित पर्यावरण में योगदान होगा।₹

उन्होंने कहा, ₹हमारे डीलरशिप पर फास्ट चार्जर लगाने से उन्हें विश्वसनीय चार्जिंग सुविधा के साथ परिचित स्थान तक पहुंच प्राप्त करने में सुविधा होती है।₹

साझेदारी पर बोलते हुए डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक निरंजन नायक ने कहा, ₹डेल्टा का लक्ष्य बेहतर कल के लिए अभिनव, स्वच्छ और ऊर्जा-कुशल समाधान प्रदान करना है। टाटा मोटर्स और थंडरप्लस के साथ यह सहयोग हमें भारत के इलेक्ट्रिक कार्गो इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण योगदान करने की अनुमति देता है। हमारी उन्नत चार्जिंग तकनीक देश भर के उपयोगकर्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहन अनुभव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।₹

थंडरप्लस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ राजीव वाईएसआर ने कहा, ₹हमारा ध्यान इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन ग्राहकों को बेहतरीन चार्जिंग समाधान उपलब्ध कराने पर है, जो सुविधा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं। यह सहयोग पूरे भारत में स्थायी परिवहन समाधान को बढ़ावा देने के हमारे मिशन के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। यह पहल पूरी तरह से हमारे अभियान #हरघरथंडर के अनुरूप है, जिसके माध्यम से हम हर घर के लिए चार्जिंग पॉइंट को किफ़ायती बनाना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराना, जिससे चार्जिंग की चिंता दूर हो।₹

यह साझेदारी टाटा मोटर्स के ऐस ईवी को सपोर्ट करने के लिए आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए तैयार की गई है, जो कि अंतिम मील डिलीवरी के लिए डिज़ाइन किया गया एक छोटा वाणिज्यिक वाहन है। टाटा के EVOGEN प्लेटफ़ॉर्म पर निर्मित ऐस ईवी में बैटरी प्रबंधन प्रणाली, फ्लीट एज टेलीमैटिक्स और बेहतरीन प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए मज़बूत घटकों सहित उन्नत तकनीक है। यह एक बार चार्ज करने पर 154 किलोमीटर की प्रमाणित रेंज का दावा करता है, जो एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित होता है जो 36 बीएचपी और 130 एनएम का टॉर्क देता है। वाहन में 208 क्यूबिक फ़ीट के कार्गो वॉल्यूम वाला एक हल्का कंटेनर भी शामिल है और पूरी तरह से लोड होने पर 22 प्रतिशत तक की ढलानों को संभाल सकता है।

टाटा मोटर्स ने पहले ही ऐस ईवी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, इसके लिए उसने अमेज़न, बिगबास्केट, सिटी लिंक, डीओटी, फ्लिपकार्ट, लेट्सट्रांसपोर्ट, मोईविंग और येलो ईवी जैसी प्रमुख कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत भर में फैले 150 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन सेवा केंद्रों के साथ, टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों की बढ़ती मांग का समर्थन करने के लिए अच्छी स्थिति में है।

मारुति ईवीएक्स के जनवरी 2025 में आने की पुष्टि

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। मारुति सुज़ुकी ने पहली बार 2023 ऑटो एक्सपो में ईवीएक्स इलेक्ट्रिक एसयूवी का प्रदर्शन किया था। इसके बाद पिछले साल जापान मोबिलिटी शो में इसका अपडेटेड वर्जन पेश किया गया। कार निर्माता ने अब उत्पादन के लिए तैयार कार के अनावरण की समयसीमा की पुष्टि की है। नई उत्पादन-स्पेक सुज़ुकी ईवीएक्स को दिल्ली में 2025 इंडिया मोबिलिटी शो में प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद इसे पहले यूरोपीय बाजार में और फिर 2025 की पहली छमाही में भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा। मारुति सुज़ुकी की पहली ऑल-इलेक्ट्रिक रेस, ईवीएक्स एक मिड-साइज़ इलेक्ट्रिक यूनिट होगी।

मारुति ने अभी तक 2025 ईवीएक्स की तकनीकी विशिष्टताओं का खुलासा नहीं किया है। यह पावरट्रेन एक बार फुल चार्ज होने पर 550 किमी की रेंज देने का दावा कर सकता है। फीचर्स की बात करें तो नई ईवीएक्स में स्प्लिट लेड हेडलैंप, बड़े एलॉय व्हील, सी-पिलर-माउंटेड रिले डोर हैंडल, इलेक्ट्रिकली स्ट्रीमर्ड फ्रंट सीट, टू-स्पोक फ्लैट-बॉटम रेजिस्टेंस व्हील, 360-डिग्री कैमरा, फ्लोटिंग सेंटर कंसोल और ड्राइव मोड के लिए सामान्य डायल दिए जा सकते हैं।

लखनऊ को अधिक पैदल यात्रियों, गैर-मोटर चालित वाहनों और इलेक्ट्रिक बसों से बनाएं स्मार्ट

परिवहन विशेष न्यूज

क्लाइमेट एजेंडा द्वारा चलाए जा रहे ग्रीन सफर अभियान के तहत लखनऊ के बर्लिंगटन स्क्वायर के पास एक होटल में क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में शहरी परिवहन व्यवस्था को स्वच्छ और समावेशी बनाने के उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया और इसमें विश्व स्तर के जाने-माने विशेषज्ञों ने भाग लिया। विशेष रूप से, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के परिवहन कार्यक्रम प्रमुख चिंतन दफ्तरदार, बैंगलोर बस पैसेंजर्स फोरम की संस्थापक सुश्री शाहीन शाशा और पीवीपी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, पुणे के निदेशक प्रोफेसर प्रसन्ना देसाई और क्लाइमेट एजेंडा की निदेशक एकता शेखर मौजूद थीं।

श्री चिंतन दफ्तरदार ने इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग स्टेशनों को सौर ऊर्जा आधारित करने की वकालत की और सभी संभव रूटों पर अधिकतम संख्या में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के महत्व पर ज़ोर दिया।

प्रोफ़ेसर प्रसन्ना देसाई ने शहर की सड़कों को बढ़ते निजी वाहनों के हिसाब से डिजाईन करने के बजाये बसों, गैर मोटर चलित वाहनों और पैदल चलने वाले यात्रियों को सड़कों पर अधिकतम संभव स्थान देने के फायदे गिनाये।

सुश्री शाहीन शाशा ने बसों और गैर-मोटर चालित वाहनों का उपयोग करने वालों का एक सार्वजनिक मंच बनाने और सरकार के संबंधित विभागों को उनकी आवश्यकताओं को समझाने पर जोर दिया।

एकता शेखर ने प्रतिभागियों से एक नेटवर्क के तहत कार्य करने और लखनऊ समेत प्रदेश के अन्य शहरों में भी यातायात प्रणाली को स्वच्छ एवं समावेशी बनाने के लिए समेकित प्रयास करने की अपील की।

कार्यशाला में स्वागत व धन्यवाद ज्ञापन रश्मि काला ने किया। इस कार्यशाला में लखनऊ समेत प्रदेश के कई अन्य शहरों के प्रतिभागी मौजूद रहे हैं। हरित सफ़र अभियान उत्तर प्रदेश और बिहार के शहरों में यातायात प्रणाली को स्वच्छ एवं समावेशी बनाने के लिए कार्यरत है। यह अभियान शहरों में होने वाले ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाकर जलवायु परिवर्तन की गति को धीमा करने के लक्ष्य पर केन्द्रित है।

सऊदी अरब बना रहा है दुनिया का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला जहाज

परिवहन विशेष न्यूज

सऊदी अरब ने स्वीडिश कंपनी कैंडेला के साथ अब तक का सबसे बड़ा सौदा किया है। किंगडम ऑफ सउदी अरबिया ने निओम सिटी प्रोजेक्ट के लिए आठ कैंडेला P-12 इलेक्ट्रिक हाइड्रोफॉइल जहाजों का ऑर्डर दिया है, जो स्टॉकहोम स्थित कंपनी के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर भी है। ये इलेक्ट्रिक शटल पानी के ऊपर चलने में सक्षम है। साथ ही यह पारंपरिक जहाजों की तुलना में 80 फीसदी कम ऊर्जा खपत करती है।

सऊदी अरब के रेगिस्तान में 'निओम' एक हाई-टेक मेगासिटी के रूप में तैयार हो रहा है। निओम की सबसे मशहूर स्कीमेटिक फीचर्स में से एक ₹द लाइन₹ है, जो गगनचुंबी इमारतों से भरे सऊदी अरब के इस नए शहर को 100 फीसदी सौर ऊर्जा पर चलाने की योजना है। इसी के तहत केएसए ने आठ इलेक्ट्रिक जहाजों का ऑर्डर दिया है। निओम ने अपने बयान में कहा, "लाल सागर के तट के साथ उत्तर-पश्चिमी सऊदी अरब में डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट निओम ने स्वीडन स्थित इलेक्ट्रिक जहाज निर्माता कैंडेला से आठ इलेक्ट्रिक शटल का ऑर्डर दिया है।"

कैंडेला पी-12 दुनिया का पहला हाई स्पीड और लंबी दूरी का इलेक्ट्रिक शटल जहाज माना जाता है। इन्हीं शटलों के जरिए यात्रियों को लाल सागर और निओम ले जाया जाएगा। कैंडेला के सीईओ और संस्थापक गुस्ताव हसेल्सकोग ने एक बयान में कहा, ₹पी-12 को शून्य-उत्सर्जन वाटर ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें ट्रेडिशनल ट्रान्सपोर्ट की तुलना में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। धीमी और ऊर्जा का कम खपत करने के साथ ये पारंपरिक घाटों वाली विरासत प्रणालियों के अलग है, कैंडेला पी-12 एक छोटी और तेज़ यूनिट है।₹

कंपनी के मुताबिक यह जहाज पहला इलेक्ट्रिक हाइड्रोफॉइल जहाज है, जो हाइड्रोफॉइल पानी के नीचे के पंखों को रेफर्ड करता है। कैंडेला पी-12 के वीडियो में जहाज पानी से इतना ऊपर दिखता है कि कुछ कोणों पर यह पानी के ऊपर तैरता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन यह पानी के ऊपर नहीं है। कैंडेला के मुताबिक जहाज के पानी के नीचे के पंखे कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं और इसे पुराने जहाजों की तुलना में 80 फीसदी कम ऊर्जा का खपत होता है।

स्टॉकहोम में केटीएच रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में किए गए एक स्टडी में पाया गया कि इलेक्ट्रिक हाइड्रोफॉइल अपने जीवन चक्र के दौरान डीजल से चलने वाले जहाजों की तुलना में 97.5 फीसदी कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं।

कैंडेला पी-12 जहाज को 2023 में लॉन्च किया गया है , जो 80 फीसदी ऊर्जा बचाने का दावा करता है। कैंडेला को इसी साल स्टॉकहोम के सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में इस्तेमाल करने की पूरी संभावना है। खास बात यह है कि इलेक्ट्रिक कैंडेला में लगा सी-पीओडी मोटर जो पानी के अंदर स्थित रहता है उससे समुद्री जीवों को नुकसान नहीं होगा।

पी-12 सबसे तेज़ और सबसे लंबी दूरी करने वाली इलेक्ट्रिक जहाज है, जो 25 मील की दूरी महज दो घंटे से तय कर लेती है। साथ ही इसकी डिजिटल उड़ान कंट्रोल सिस्टम तेज लहरों में भी सफर को आसान बनाती है।

पी-12 जहाज करीब 40 फीट लंबा है। इसमें पायलट के अलावा 30 लोग सफर कर सकते हैं। कैंडेला पी-12, जिसे पिछले साल लॉन्च किया गया था, को इस साल के आखिर में स्टॉकहोम की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में पेश किए जाने और 2025 और 2026 की शुरुआत में नियोम तक पहुंचाए जाने की उम्मीद है।

अमृतसर में राही योजना के अंतर्गत डीजल ऑटो को ई-ऑटो में बदलने में रहा विफल

परिवहन विशेष न्यूज

पिछले तीन सालों में अमृतसर में ऑटो-रिक्शा के पुनरुद्धार राही योजना के तहत केवल 950 चालकों ने डीजल ऑटो-रिक्शा से ई-ऑटो पर स्विच किया है। अमृतसर स्मार्ट सिटी लिमिटेड इस परियोजना को लागू करने में विफल रहा, क्योंकि 40,000 से अधिक अनधिकृत डीजल ऑटो और ई-रिक्शा अभी भी सड़कों पर चल रहे हैं।

अमृतसर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा शुरू की गई राही परियोजना को तीन साल से अधिक हो चुके हैं। इस परियोजना के तहत डीजल ऑटो चालकों को अपने पुराने वाहन छोड़कर ई-ऑटो खरीदना था। इसके एवज में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चालकों को 1.25 लाख रुपये और पुराने डीजल ऑटो स्क्रैप के लिए 15,000 रुपये की सब्सिडी की पेशकश की गई थी। बाकी की राशि आसान किस्तों में चुकाने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को सूचीबद्ध किया गया था।

इस योजना के तहत पहले 7,440 ई-ऑटो को सब्सिडी के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके बाद यह संख्या और कम हो गई। इसके बावजूद ई-ऑटो के लिए बहुत कम ग्राहक आए। अमृतसर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने राही प्रोजेक्ट के लिए 21 करोड़ रुपए आरक्षित किए। वर्तमान में शहर की सड़कों पर 40,000 से अधिक डीजल ऑटो चल रहे हैं। नगर निगम, जिला प्रशासन और यातायात पुलिस के अधिकारियों ने डीजल ऑटो के संचालन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की और कुछ डीजल ऑटो-रिक्शा को अवैध घोषित करते हुए जब्त भी किया, लेकिन डीजल ऑटो ऑपरेटर यूनियनों ने सड़क जाम कर दिया और नरमी बरतने के लिए राजनीतिक दबाव बनाया।

राही परियोजना के तहत अमृतसर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए और डीजल ऑटो चालकों के परिवार के सदस्यों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं भी पेश कीं, लेकिन संतोषजनक परिणाम नहीं मिले। काफी प्रयासों के बाद भी करीब 950 ई-ऑटो ही बिक पाए।

अमृतसर स्मार्ट सिटी लिमिटेडL ने राही परियोजना के तहत महिला चालकों के लिए पिंक ऑटो परियोजना भी शुरू की है। इसका व्यापक प्रचार भी किया गया है। 90 प्रतिशत की भारी सब्सिडी देने के बावजूद, महिला चालकों को केवल 70 पिंक ऑटो आवंटित किए गए हैं, जिन्हें उनके पुरुष परिवार के सदस्य चला रहे हैं।

स्थानीय कार्यकर्ता एसके शर्मा ने कहा, "सरकार की पहल के विपरीत, डीजल ऑटो चालक स्थानीय स्तर पर बने अनधिकृत ई-रिक्शा खरीद रहे हैं। अधिकारियों को डीजल ऑटो और अनधिकृत ई-रिक्शा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जो कि बहुत सस्ते हैं।"

कोई भी पुरुष देवता नहीं होता

अमनजोत कौर रामूवालिया

पिछले दिनों हुई कई गैंग रेप की घटनाएं देश के लिए दर्दनाक और शर्मनाक घटनाएं हैं। बंगाल में गैंग रेप की घटना इतनी भयानक है कि रूह कांप जाती है, महिला होने से भी डर लगता है। पूरा देश त्राहि-त्राहि कर रहा है। पी.जी.आई. चंडीगढ़ और देशभर में हड़तालें चल...

पिछले दिनों हुई कई गैंग रेप की घटनाएं देश के लिए दर्दनाक और शर्मनाक घटनाएं हैं। बंगाल में गैंग रेप की घटना इतनी भयानक है कि रूह कांप जाती है, महिला होने से भी डर लगता है। पूरा देश त्राहि-त्राहि कर रहा है। पी.जी.आई.चंडीगढ़ और देशभर में हड़तालें चल रही हैं। डाक्टर और नर्स सभी डरे हुए हैं। दिसंबर 2012 में दिल्ली में एक लड़की के साथ 6 लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार और हत्या के निर्भया मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस घटना के बाद भी ऐसे जघन्य अपराध के लिए मौत की सजा का सख्त प्रावधान किया गया। लेकिन यह देश का दुर्भाग्य है कि बलात्कार जैसी घटनाओं के खिलाफ फांसी की सजा के प्रावधान के बावजूद न केवल देश में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक आंकड़े बढ़े हैं, बल्कि बलात्कार और हत्या जैसी घटनाओं में भी कोई कमी नहीं आई है।

ऐसी घटनाओं के लिए सिर्फ राजनीतिक दलों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। करीब 90 फीसदी समाज में हमारा समाज, सामाजिक ढांचा आज भी पुरुषों को ज्यादा प्राथमिकता देता है। हमारे समाज की इसी भावना ने हमें बहुत बर्बाद किया है। महिलाओं और बेटियों को नीचा दिखाना और पुरुषों को समाज का अधिक महत्वपूर्ण सदस्य माना जाता है। 58 साल की उम्र में भी मैं इस भावना से ग्रस्त रहती हूं और सोचती हूं कि समाज की महिलाओं को यह हर दिन होता होगा। मेरी इकलौती बच्ची भी डाक्टर है, जब वह रात में ड्यूटी पर जाती थी तो मुझे और मेरे पति को नींद नहीं आती थी। हम रात 2 बजे भी उसका हालचाल पूछने अस्पताल जाते थे। मैं समझती हूं कि सभी माता-पिता हमारी तरह चिंतित होंगे कि उनकी बेटी जो लगातार 19-19 घंटे पढ़ाई करती है और लोगों की सेवा करने का जज्बा रखती है, उसकी सुरक्षा तो बनती है। दरअसल, घर में पैदा होने वाले लड़के को हम कुछ नहीं सिखाते, बस पुरुष होने से ही वह घर का प्रमुख बन जाता है। एक बच्चे के रूप में, वह अपनी बहनों से लेकर अपनी मां तक वह शासन करता है और जब वह बड़ा होता है, तो वह अपनी पत्नी और बच्चों की सारी पारिवारिक संपत्ति का मालिक बन जाता है।

हमारी शिक्षा प्रणाली में बड़े सुधारों की जरूरत है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में समाज में सोच-विचार के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता, जो लड़की समानता के अधिकार के लिए लड़ती है, वह लड़ती-लड़ती औरत बन जाती है। क्या कभी किसी पुरुष को अपने अधिकार के लिए लडने की जरूरत पड़ी? दिमाग पर उतना ही बोझ डालो जितना सदियों से इसकी उत्पत्ति हुई है। मुझे लगता है कि इसका कारण यह है कि पुरुषों में महिलाओं की तुलना में अधिक शारीरिक शक्ति होती है। लेकिन मानसिक और सहनशक्ति की दृष्टि से महिलाएं पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत होती हैं। एक महिला केवल शारीरिक रूप से ही पुरुष से कमजोर होती है। भले ही गुरु नानक जैसे महापुरुषों ने महिलाओं के पक्ष में कहा हो, 'सो क्यों मंदा आखिए, जित जम्मे राजन' लेकिन फिर भी हम हर क्षेत्र में काम करते हुए भी बहुत पीछे और कमजोर हैं। अगर हम भारतीय पुरुष की बात करें तो भारतीय पुरुष अपने मन में खड़ा-खड़ा ही स्त्री का बलात्कार कर दे।

जैसे-जैसे शरीर मजबूत होता जाता है, वैसे-वैसे उसकी बुद्धि और उग्रता भी बढ़ती जाती है। जब तक घरों में अच्छे संस्कार और नियम होते हैं, तब तक वे लोग अच्छे होते हैं। लेकिन जहां मार-पिटाई, गाली-गलौच और बुरे शब्द बोले जाते हैं, वहां इंसान भी पतित होकर जानवर बन जाता है। मुझे लगता है कि मुफ्त में रोटी बांटने से पहले कम से कम स्कूल में सामाजिक शिक्षा देना बहुत जरूरी है। जिसमें अभिभावकों को भी पाठ पढ़ाया जाए और जो लोग शिविर में जाते हैं या मुफ्त भोजन पाते हैं उन्हें बैठकर सामाजिक शिक्षा के बारे में एक वीडियो देखने के लिए कहा जाए। 21वीं सदी में हम दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक बनने जा रहे हैं। लेकिन सोच बदलना बहुत जरूरी है अक्सर बात ड्रैस पर आकर खत्म हो जाती है। मैं दुनिया के कई देशों में गई हूं और देखा है कि बुर्के में रहने वाली महिलाओं के साथ भी बलात्कार होता है। अमरीका, कनाडा या इटली जैसे देशों में सड़क पर बिकनी पहनकर चलने वाली लड़कियों को कोई तुच्छ नहीं समझता। कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करता। ब्राजील जैसे गरीब और कम पढ़े-लिखे देश में महिलाओं को पूरी आजादी है और समानता का अधिकार है।

हम जो अति धार्मिक हैं, धर्म के बड़े ठेकेदार कहलाते हैं। क्या हमारे मदरसों में कोई सामाजिक शिक्षा भी दी जाती है? बस यही सिखाया जाता है कि हमारा धर्म सबसे अच्छा है और बाकी सब काफिर हैं। महिलाओं का अपमान करना ही सिखाया जाता है। मंदिर और गुरुद्वारे सिखाते हैं कि महिलाओं को समान अधिकार हैं, जितना कि गुरु ग्रंथ साहिब और गीता महिलाओं का सम्मान करने के लिए कहते हैं, लेकिन क्या इस अवधारणा को आम जीवन में माना जाता है या नहीं? क्या आपने कभी किसी पुजारिन को किसी बड़े मंदिर में या ग्रंथी सिंहनी गुरु के घर में देखी है? मैं समाज और धर्म के ठेकेदारों से पूछना चाहती हूं कि आप, जिन्होंने पुरुष और महिला के बीच यह अंतर पैदा किया है, इसे कब बराबर होने देंगे। महिलाएं कब आगे बढ़ेंगी और समान अधिकार देंगी? अक्सर धर्म और समाज के ठेकेदार यह कहते सुने जाते हैं, 'शर्म तो आंखों में होती है' क्या यह शर्म पुरुषों के लिए नहीं है या सिर्फ महिलाओं के लिए है जिन्हें हर हाल में अग्निपरीक्षा से गुजरना पड़ता है?

सुझाव : हालांकि डाक्टरों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जता चुका है, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे बुरे समय में देश की सरकार को एन.जी.ओ. और राजनीतिक दलों के साथ मिलकर हर गांव-शहर, हर गली-मोहल्ले में एक कार्यक्रम बनाना चाहिए। पुरुष को सख्ती से डांटना और समझाना चाहिए और उसे महिला का सम्मान करने और महिला को सुरक्षित रखने का जरिया बनाना चाहिए। छोटे पैमाने पर 'सामाजिक सुधार' अभियान चलाए जाने चाहिएं। बड़े स्तर पर काम किया जाना चाहिए। महिलाओं को बताया जाना चाहिए कि पुरुष कोई देवता नहीं है। (लेखिका भाजपा कार्यकारिणी कमेटी की सदस्य हैं।

संपादक की कलम से

'महिलाओं और बच्चियों के विरुद्ध अपराध' 'विदेशों में भी हो रही भारत की बदनामी'

ऐसा लगता है कि जैसे हमारे देश में बच्चियों और महिलाओं पर साढ़ेसाती आई हुई है। पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डाक्टर के बलात्कार और हत्या को लेकर देशव्यापी बवाल के कारण लंदन में धर्मार्थ संस्थाओं, प्रवासी संगठनों और भारतीय छात्रों द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं। भारत में मात्र पिछले 3 दिनों में सामने आई घटनाएं निम्र में दर्ज हैं:

* 22 अगस्त को राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में एक 4 वर्षीय मासूम की मां जब किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी तो उसके 35 वर्षीय रिश्तेदार ने मासूम से बलात्कार कर डाला।

* 22 अगस्त को ही बिहार के बेतिया में एक नृसग कालेज के प्रिंसिपल मनीष कुमार जायसवाल को लड़कियों से अश्लील हरकतें करने, आफिस में शराब पीने तथा होस्टल की छत पर मालिश करवाने के आरोप में निलम्बित किया गया।

* 22 अगस्त को ही उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर जिले के 'पुवायां' थाना क्षेत्र में एक युवक ने एक मकान में घुस कर एक महिला से बलात्कार कर डाला जब उसका पति घर से बाहर गया हुआ था।

* 22 अगस्त को ही महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में घर से लापता एक 10 वर्षीय लड़की का शव गन्ने के खेत से बरामद हुआ जिसकी हत्या करने से पहले उससे बलात्कार किया गया था।

* 23 अगस्त को असम के नागांव जिले के 'धींग' इलाके में रात लगभग 8 बजे ट्यूशन से साइकिल पर घर लौट रही 14 वर्षीय एक हिन्दू किशोरी से 3 लोगों ने बलात्कार कर डाला।

* 23 अगस्त को ही उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक नवविवाहित मुस्लिम महिला द्वारा नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करने पर उसके ससुराल वालों ने उसके चेहरे पर खौलती हुई दाल फैंक कर उसका चेहरा जलाने के अलावा पति ने 'तीन तलाक' दे दिया।

* 23 अगस्त को ही महाराष्ट्र के बदलापुर में एक स्कूल में 3 और 4 वर्ष की 2 मासूम बच्चियों के यौन उत्पीडन के मामले में सरकार द्वारा गठित 2 सदस्यीय पैनल के अनुसार इन बच्चियों का एक बार नहीं बल्कि 15 दिनों में कई बार यौन शोषण किया गया जिससे उनकी योनि की झिल्ली फट गई।

* 23 अगस्त को ही छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्कूल से लौट रही एक 13 वर्षीय नाबालिग को लिफ्ट देने के बहाने जंगल में ले जाकर उससे बलात्कार करने के आरोप में एक 30 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

* 23 अगस्त के दिन ही चंडीगढ़ में एक स्कूल बस ड्राइवर मोहम्मद रज्जाक को 12वीं कक्षा की छात्रा की तस्वीरों से छेड़छाड़ के जरिए उसे ब्लैकमेल करके उससे बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

* 23 अगस्त को ही महाराष्ट्र में चंद्रपुर जिले के 'नागभीड़' कस्बे में मानसिक रूप से कमजोर एक 27 वर्षीय युवती से सामूहिक बलात्कार करने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार व एक नाबालिग लड़के को हिरासत में लिया गया।

* 23 अगस्त रात को कर्नाटक में उडुपी जिले के कारकल में एक 24 वर्षीय युवती को अपहरण कर नशीला पदार्थ देने के बाद सुनसान जगह पर ले जाकर बलात्कार कर दिया गया।

* 24 अगस्त को महाराष्ट्र में पुणे के पिंपरी-ड्डष्चचवड में एक निजी स्कूल में 12 वर्षीया छात्रा के यौन उत्पीडन के आरोप में एक अध्यापक और 7 अन्य को गिरफ्तार किया गया।

* 24 अगस्त को ही असम में 'सोनितपुर' जिले में सैर पर निकली 2 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करने के आरोपी ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की जिसे पुलिस ने गोली मार कर घायल कर दिया।

* 24 अगस्त को ही कोयम्बटूर के एक स्कूल में सातवीं, आठवीं तथा नौवीं कक्षा की 9 छात्राओं के यौन शोषण के आरोप में नटराजन नामक एक अध्यापक को तथा शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई न करने के आरोप में स्कूल के हैडमास्टर और क्लास टीचर को गिरफ्तार किया गया। प्रतिदिन हो रही बलात्कार की घटनाओं ने न सिर्फ देश में नारी जाति की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्र खड़े कर दिए हैं बल्कि विदेशों में भी हमारी बदनामी होने लगी है।

राय

'स्कूली बसों में बच्चों की सुरक्षा' 'पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का सही आदेश'

अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए माता-पिता स्कूली बसों का सहारा लेते हैं। कुछ बसें स्कूलों के प्रबंधकों द्वारा चलाई जाती हैं जबकि कुछ बसें वे ठेके पर लेते हैं। इनके ड्राइवरों व अन्य स्टाफ द्वारा नशे में वाहन चलाने, बच्चियों से छेड़छाड़ और यौन...

अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए माता-पिता स्कूली बसों का सहारा लेते हैं। कुछ बसें स्कूलों के प्रबंधकों द्वारा चलाई जाती हैं जबकि कुछ बसें वे ठेके पर लेते हैं। इनके ड्राइवरों व अन्य स्टाफ द्वारा नशे में वाहन चलाने, बच्चियों से छेड़छाड़ और यौन उत्पीडन आदि की घटनाएं होती रहती हैं। ऐसी कोई घटना होने पर कई बार स्कूल प्रबंधक यह कह कर पल्ला झाड़ लेते हैं कि बस उनकी नहीं बल्कि ठेके पर ली हुई थी।

इसी का संज्ञान लेते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा और पंजाब की सरकारों तथा चंडीगढ़ के प्रशासन को 'सुरक्षित स्कूल वाहन नीति' के अंतर्गत सभी स्कूली बसों में सी.सी.टी.वी. कैमरे, स्पीड गवर्नर व हाइड्रॉलिक दरवाजों का प्रावधान करने का निर्देश देते हुए पूछा था कि उनकी स्कूली बसों के स्टाफ को 'बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम' की ट्रेनिंग दी जा सकती है या नहीं। इसी सिलसिले में मान्य चीफ जस्टिस शील नागू तथा जस्टिस विकास सूरी पर आधारित पीठ ने हरियाणा और पंजाब की सरकारों तथा यू.टी. चंडीगढ़ के प्रशासन से अपने-अपने क्षेत्र में 'सुरक्षित स्कूल वाहन नीति' को सही तरीके से लागू करवाने का आदेश देते हुए कोर्ट मित्र के समक्ष 24 अक्तूबर से पहले अपना जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

माननीय न्यायाधीशों के अनुसार यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनके क्षेत्र में आने वाले स्कूलों में इस दिशा-निर्देश के पालन को सुनिश्चित करें। नियमों का पालन नहीं करने पर सरकार ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द करने का निर्णय ले सकती है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि बस स्कूल की अपनी न होकर किसी ठेकेदार की है, तो भी स्कूल प्रबंधन की यह जिम्मेदारी है कि वह 'सुरक्षित स्कूल वाहन नीति' का पालन सुनिश्चित करे। स्कूल बस दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप बच्चों की जान को खतरे तथा बसों के ड्राइवर व अन्य स्टाफ द्वारा बच्चियों के यौन शोषण के समय-समय पर सामने आते रहने वाले मामलों के दृष्टिगत पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का उक्त आदेश सही है जिसके लिए न्यायाधीश साधुवाद के पात्र हैं।

आरक्षण प्रणाली का उपयोग चुनावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता है

उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि राज्य को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण करने का अधिकार है। इसका मतलब है कि राज्य एस.सी. श्रेणियों के बीच अधिक पिछड़े लोगों की पहचान कर सकते हैं और कोटे के...

उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि राज्य को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण करने का अधिकार है। इसका मतलब है कि राज्य एस.सी. श्रेणियों के बीच अधिक पिछड़े लोगों की पहचान कर सकते हैं और कोटे के भीतर अलग कोटा के लिए उन्हें उप-वर्गीकृत कर सकते हैं। अनुसूचित जातियों में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आरक्षण के बावजूद अन्य अनुसूचित जातियों की तुलना में बहुत कम प्रतिनिधित्व मिला है।

अनुसूचित जातियों के भीतर यह असमानता कई रिपोर्टों में भी सामने आई है और इस मुद्दे को हल करने के लिए विशेष कोटा तैयार किया गया है। आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और बिहार में सबसे अति पिछड़े दलितों के लिए विशेष कोटा शुरू किया गया था। समय-समय पर राजनीतिक विद्वानों ने जातिगत स्तर पर सबसे निचले तबके को लाभ पहुंचाने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में आरक्षण की प्रभावशीलता के बारे में बहस की है।

मामले पर नियंत्रण रखने के लिए, संवैधानिक निर्माताओं ने राष्ट्रपति को (अनुच्छेद 341 में) एक सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से अस्पृश्यता के ऐतिहासिक अन्याय से पीड़ित 'जातियों-नस्लों या जनजातियों' को एस.सी. के रूप में सूचीबद्ध करने की अनुमति दी।

अनुसूचित जाति समूहों को संयुक्त रूप से शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में 15 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में एस.सी. सूची में कुछ समूहों को दूसरों की तुलना में कम प्रतिनिधित्व दिया गया है।

राज्यों ने इन समूहों को अधिक सुरक्षा देने का प्रयास किया है, लेकिन यह मुद्दा न्यायिक जांच में चला गया है और इस फैसले के साथ एस.सी. ने समाज के कुछ वर्गों तक पहुंचने के लिए जातियों जनजातियों नस्लों को उप-वर्गीकृत करने के राज्यों के अधिकारों को बरकरार रखा है जो अन्यथा क्रीमीलेयर पहले से ही ऐसे प्रावधानों का लाभ उठा रहा है जिसके कारण यह संकट में पड़ जाता है। वर्तमान आरक्षण नीति के साथ समस्या यह है कि ज्यादातर अमीर और प्रभावशाली पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण योजना से अवसर मिल रहे हैं और लाभ हो रहा है जबकि गरीब पिछड़े वर्ग के लोग अभी भी अपने लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं।

आरक्षण प्रणाली इतनी भ्रष्ट है और इसका उपयोग चुनावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकारात्मक तरीके से किया जाता है कि यह दलितों और उन लोगों की मदद करने और उनके उत्थान के अपने वास्तविक प्रचार को पूरा करने में विफल रहता है जो स्वतंत्रता के समय सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े थे। सबसे अधिक हाशिए पर पड़े और वंचितों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए आरक्षण योजनाओं की आवश्यकता है जो उनका मानवाधिकार है। 1978-79 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले दलित वर्ग का प्रतिशत 51.32 प्रतिशत था जो 1993-94 में घटकर 35.97 प्रतिशत हो गया, हालांकि यह अभी भी राष्ट्रीय गरीबी औसत से ऊपर था।

आरक्षण ने हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लोगों को इस मायने में भी मदद की है कि इससे स्नातक, स्नातकोत्तर, तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उनका नामांकन बढ़ गया है। इन श्रेणियों में अनुसूचित जाति के नामांकन का प्रतिशत 1978-79 में 7.08 प्रतिशत था जो 1995-96 में बढ़कर 13.30 प्रतिशत हो गया। समानता के बिना योग्यता तंत्र निरर्थक है। सबसे पहले सभी लोगों को समान स्तर पर लाया जाना चाहिए, चाहे योग्यता की परवाह किए बिना यह एक वर्ग को ऊपर उठाता है या दूसरे को नीचे गिराता है। प्रवेश बाधाओं में छूट देकर योग्यता तंत्र को प्रदूषित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि केवल योग्य उम्मीदवारों को ही वंचितों को वित्तीय सहायता देकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

आर्मेनिया-अजरबैजान संघर्ष की ऐतिहासिक जड़ें

काकेशस क्षेत्र पूर्वी यूरोप में काला सागर और कैस्पियन सागर के किनारे स्थित एक विशाल क्षेत्र है। इसमें दक्षिणी रूस और जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान के स्वतंत्र राष्ट्र शामिल हैं ये सभी तत्कालीन सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य (स्स्क्र) के हिस्से थे।...

काकेशस क्षेत्र पूर्वी यूरोप में काला सागर और कैस्पियन सागर के किनारे स्थित एक विशाल क्षेत्र है। इसमें दक्षिणी रूस और जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान के स्वतंत्र राष्ट्र शामिल हैं ये सभी तत्कालीन सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य (स्स्क्र) के हिस्से थे। जबकि भौतिक रूप से यह क्षेत्र यूरोप, एशिया, रूस और मध्य पूर्व के बीच स्थित है, जातीय-धार्मिक रूप से यह सीमा रेखा पर है जहां इस्लाम और ईसाई धर्म का सामना होता है। सैद्धांतिक रूप से यह वह सीमा है जहां पूर्ण लोकतंत्र नहीं होने पर भी अखंड अधिनायकवाद का सामना करना पड़ता है।

आर्मेनिया में ईसाइयों की संख्या बहुत ज्यादा है, जहां 97 प्रतिशत लोग आर्मेनियाई अपोस्टोलिक धर्म का पालन करते हैं, जो पहली शताब्दी ई. में स्थापित सबसे पुराने ईसाई चर्चों में से एक है। दूसरी ओर, अजरबैजान में 96 प्रतिशत मुस्लिम हैं, जहां 65 प्रतिशत लोग शिया इस्लाम का पालन करते हैं और बाकी लोग सांप्रदायिक रूप से सुन्नी हैं। जॉर्जिया का चार-पांचवां हिस्सा भी आस्था से रूढ़िवादी ईसाई है। सदियों से, नागोर्नो-करबाख क्षेत्र रूढ़िवादी ईसाई रूसी साम्राज्य, सुन्नी ओटोमन साम्राज्य और शिया ईरानी साम्राज्य द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले 3 प्रमुख सभ्यतागत उपभेदों के बीच एक सीमा के रूप में कार्य करता रहा है। इसलिए यह क्षेत्र एक जातीय आर्मेनियाई परिक्षेत्र है जो सदियों से विवाद का केंद्र बिंदू रहा है। इस प्रकार नागोर्नो-करबाख को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच मतभेद इतिहास में गहराई से समाया हुआ है। 1805 में, यह क्षेत्र कुरेकचाय की संधि के तत्वावधान में निर्णायक रूप से रूसी साम्राज्य का हिस्सा बन गया। सोवियत काल के दौरान, नागोर्नो-करबाख को आधिकारिक तौर पर अजरबैजान सोवियत समाजवादी गणराज्य के भीतर एक स्वायत्त ओब्लास्ट के रूप में नामित किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से अर्मेनियाई आबादी के बावजूद उचित मात्रा में क्षेत्रीय स्वायत्तता थी।

इस प्रशासनिक निर्णय ने आर्मेनियाई बहुमत को राजनीतिक रूप से हाशिए पर महसूस कराकर भविष्य में कलह के बीज बो दिए। हालांकि सोवियत शासन के तहत तनाव कुछ हद तक प्रबंधित किया गया था, लेकिन वे कभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए। सोवियत संघ के विघटन के बाद, जब आर्मेनिया और अजरबैजान ने स्वतंत्रता की घोषणा की, तो नागोर्नो-करबाख की स्थिति एक बार फिर से विवाद का विषय बन गई। 1988 में, नागोर्नो-करबाख की क्षेत्रीय परिषद ने आर्मेनिया के साथ एकजुट होने के लिए मतदान किया, जिससे ड्डष्हसक झड़पें हुईं और एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध हुआ जो 1991 से 1994 तक चला। युद्ध एक युद्धविराम के साथ समाप्त हुआ जिसने आर्मेनिया को नागोर्नो-करबाख के नियंत्रण में छोड़ दिया।

हालिया घटनाक्रम : सितंबर 2023 में नागोर्नो-करबाख क्षेत्र में तनाव बढने से एक बार फिर से ठंडे पड़े आर्मेनिया-अजरबैजान संघर्ष को एक नए विनाशकारी चरण में धकेल दिया। दिसंबर 2022 में अजरबैजान द्वारा लाचिन कॉरिडोर को बाधित करने से संकट की शुरूआत हुई, जो आर्मेनिया को इस क्षेत्र से जोडने वाली एकमात्र सड़क है। नाकाबंदी के कारण नागोर्नो-करबाख में आवश्यक आपूर्ति की भारी कमी हो गई। अजरबैजान ने स्पष्ट रूप से नाकाबंदी को तर्कसंगत बनाने का प्रयास किया और आर्मेनिया पर सैन्य आपूर्ति के परिवहन के लिए कॉरिडोर का उपयोग करने का आरोप लगाया, एक ऐसा दावा जिसे आर्मेनिया ने नकार दिया। रूसी शांति सैनिकों की कम उपस्थिति से स्थिति और भी खराब हो गई, क्योंकि मॉस्को का ध्यान यूक्रेन के साथ अपने संघर्ष पर चला गया। 19 सितंबर, 2023 को स्थिति एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई, जब अजरबैजानी सेना ने एक आक्रामक अभियान शुरू किया। इस कार्रवाई का समापन आर्मेनियाई-बहुल नागोर्नो-करबाख पर अजरबैजान के कब्जे के रूप में हुआ, जिसने इसकी 30 साल की वास्तविक स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया और एक सप्ताह के भीतर 100,000 से अधिक जातीय आर्मेनियाई लोगों के सामूहिक पलायन को गति दी।

एक बार 'स्थिर' विवाद माना जाने वाला यह संघर्ष अब महत्वपूर्ण स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक निहितार्थों के साथ नए सिरे से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित कर रहा है। रूस, जो पारंपरिक रूप से इस क्षेत्र में एक संतुलनकारी शक्ति है, आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों के साथ एक जटिल संबंध बनाए रखता है। यह दोहरा दृष्टिकोण रूस को काकेशस में अपने रणनीतिक हितों की रक्षा करते हुए दोनों देशों पर प्रभाव बनाए रखने की अनुमति देता है। कई बैठकों और प्रस्तावों के बावजूद, दोनों पक्षों के अडियल रवैये, क्षेत्रीय शक्तियों के जटिल भू-राजनीतिक हितों और आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच गहरे अविश्वास के कारण स्थायी शांति नहीं बन पाई है।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम से कर्मचारियों की होगी चांदी, सरकार का भी घटेगा बोझ

परिवहन विशेष न्यूज

एनपीएस के तहत पेंशन फंड में सरकार 14 प्रतिशत देती है तो कर्मचारी अपने वेतन और महंगाई भत्ता का 10 प्रतिशत का योगदान देती है। इस पूरे फंड को कर्मचारी अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है। मतलब उस फंड का पैसा कहां लगेगा यह कर्मचारी तय कर सकता है। यूपीएस में 10 प्रतिशत कर्मचारी तो 18 .5 प्रतिशत सरकार अपना योगदान देगी।

नई दिल्ली। ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) के बढ़ते भार को देखते हुए ही सरकार ने वर्ष 2004 में नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) की शुरुआत की थी ताकि सरकार पर बढ़ते आर्थिक बोझ को कम किया ज सके। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 1991 में केंद्र का पेंशन बिल 3272 करोड़ तो राज्य का 3131 करोड़ का था जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर बढ़कर 1,90,886 करोड़ हो गया तो राज्यों का बिल 3,86001 करोड़ हो गया।

एनपीएस के तहत पेंशन फंड में सरकार 14 प्रतिशत देती है तो कर्मचारी अपने वेतन और महंगाई भत्ता का 10 प्रतिशत का योगदान देती है। इस पूरे फंड को कर्मचारी अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है। मतलब उस फंड का पैसा कहां लगेगा, यह कर्मचारी तय कर सकता है। यूपीएस में 10 प्रतिशत कर्मचारी तो 18.5 प्रतिशत सरकार अपना योगदान देगी। सूत्रों के मुताबिक कर्मचारी इस 28.5 प्रतिशत में से 20 प्रतिशत फंड को मैनेज कर सकेगा, बाकी के 8.5 प्रतिशत फंड को सरकार अपने हिसाब से मैनेज करेगी। इस वजह से भविष्य में सरकार पर पेंशन का भार कम आएगा।

ओपीएस में इस प्रकार के फंड की कोई व्यवस्था नहीं थी और सरकार ही पूरी तरह से कर्मचारियों की पेंशन का बोझ उठाती थी। आगामी एक अप्रैल से लागू होने वाली यूपीएस में नौकरी के अंतिम वर्ष के औसत सैलरी का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में निर्धारित होगा। जबकि ओपीएस में अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत निर्धारित किया जाता था। यहां पर थोड़ा अंतर है क्योंकि अंतिम वर्ष में प्रमोशन मिलने पर सैलरी अगर बढ़ जाती है तो उस सैलरी का 50 प्रतिशत पेंशन नहीं मिलकर उस साल के औसत वेतन का 50 प्रतिशत निर्धारित होगा। एनपीएस में पेंशन की कोई सीमा निर्धारित नहीं थी और यह राशि कुछ भी हो सकती थी।

यूपीएस में 10 साल नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट के बाद कम से कम 10,000 रुपए पेंशन तो हर हाल में मिलेगी। पेंशनर्स के निधन के बाद उनके परिवार को उउनकी आखिरी पेंशन की 60 प्रतिशत राशि दी जाएगी। एनपीएस में ऐसी व्यवस्था नहीं थी।

अगले हफ्ते होगी रिलायंस की AGM, क्या जियो और रिलायंस रिटेल के आईपीओ का होगा एलान?

RIL ने अपनी 2022 AGM में न्यू एनर्जी में 75000 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट का एलान किया था। वहीं 2023 AGM में मुकेश अंबानी ने कहा था कि RIL न्यू एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को बनाने के लिए कमिटेड कैपिटल का इस्तेमाल करेगी। इस बार की AGM में मुकेश अंबानी रिलायंस की सहयोगी कंपनियों की शेयर मार्केट की लिस्टिंग के बारे में ज्यादा जानकारी साझा कर सकते हैं।

नई दिल्ली। अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी के मालिकाना हक वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) की सालाना आम बैठक (AGM) अगले हफ्ते वाली है। इसमें है। एशिया के सबसे अमीर शख्स और RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) शेयरहोल्डर्स को संबोधित करेंगे। इस दौरान वह रिलायंस की सहयोगी कंपनियों की शेयर मार्केट की लिस्टिंग के बारे में ज्यादा जानकारी साझा कर सकते हैं।

एजीएम पर क्या है एनालिस्टों की राय

घरेलू ब्रोकरेज JM फाइनेंशियल का कहना है कि रिलायंस की AGM से मुख्य उम्मीदें रिटेल और डिजिटल बिजनेस की लिस्टिंग के लिए टाइमलाइन पर अपडेट मिलना है। कंपनी O2C बिजनेस में पोटेंशियल स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल्स के बारे में भी बात कर सकती है।

वहीं, पिछले दिनों जेफरीज ने एक नोट में कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के टेलीकॉम बिजनेस यानी रिलायंस जियो इंफोकॉम (जियो) की पब्लिक लिस्टिंग पर वैल्यू 112 अरब डॉलर हो सकती है। इसके आईपीओ का निवेशकों से लेकर एनालिस्ट बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

बोफा सिक्योरिटीज के एनालिस्टों का कहना है कि उन्हें न्यू एनर्जी बिजनेस पर व्यापक अपडेट की उम्मीद है, क्योंकि अगले 12 महीनों में RIL का ध्यान न्यू एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को शुरू करने और लोकल लेवल पर सप्लाई चेन बनाने पर है।

रिलायंस की पिछले एजीएम में क्या हुआ था?

रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी ने पिछले कुछ AGM में संकेत दिया है कि कंपनी 2025 में ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ आगे बढ़ना शुरू करेगी। यह न्यू एनर्जी इकोसिस्टम इस बदलाव का हिस्सा है, जिसमें सोलर पीवी गीगा फैक्ट्री का चरणबद्ध संचालन भी होगा।

RIL ने अपनी 2022 AGM में न्यू एनर्जी में 75,000 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट का एलान किया था। वहीं, 2023 AGM में मुकेश अंबानी ने कहा था कि RIL न्यू एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को बनाने के लिए कमिटेड कैपिटल का इस्तेमाल करेगी।

नई पीढ़ी के हाथ मुकेश अंबानी की विरासत

मुकेश अंबानी ने पिछले साल घोषणा की थी कि उनके तीनों बच्चे बोर्ड में नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की भूमिका में रहेंगे। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वह अगले पांच साल तक कारोबार का नेतृत्व करना जारी रखेंगे और अगली पीढ़ी को मार्गदर्शन देंगे।

सेबी के आदेश की समीक्षा कर रहे अनिल अंबानी, उठाएंगे उचित कदम

रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े एक मामले में सेबी के 11 अगस्त 2022 के अंतरिम आदेश का पालन करने के लिए अनिल अंबानी ने रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और रिलायंस पावर लिमिटेड के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया था। प्रवक्ता ने कहा कि अनिल अंबानी सेबी की ओर से 22 अगस्त को दिए अंतिम आदेश की समीक्षा कर रहे हैं।

नई दिल्ली। उद्योगपति अनिल अंबानी कैपिटल मार्केट रेग्युलेटर सेबी के आदेश की समीक्षा कर रहे हैं। वे कानूनी सलाह के आधार पर उचित कदम उठाएंगे। अनिल अंबानी के प्रवक्ता ने रविवार को यह जानकारी दी। सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस के धन की हेराफेरी के मामले में अनिल अंबानी को शेयर बाजारों से पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।

प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े एक मामले में सेबी के 11 अगस्त, 2022 के अंतरिम आदेश का पालन करने के लिए अनिल अंबानी ने रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और रिलायंस पावर लिमिटेड के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया था। वह पिछले ढाई वर्षों से उक्त अंतरिम आदेश पालन कर रहे हैं। प्रवक्ता ने कहा कि अनिल अंबानी सेबी की ओर से 22 अगस्त को दिए अंतिम आदेश की समीक्षा कर रहे हैं और कानूनी सलाह के अनुसार अगला कदम उठाएंगे।

सेबी ने अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अनिल अंबानी के अलावा 24 अन्य पर भी पांच वर्ष का प्रतिबंध और जुर्माना लगाया गया है। वहीं, रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने कहा कि उसका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। सेबी ने अपने आदेश में हमें कोई निर्देश नहीं दिया है।

कैशलेस ट्रांजेक्शन पकड़ रहा रफ्तार, डिजिटल बैंकिंग को प्राथमिकता दे रहे उपभोक्ता

केंद्र सरकार को कैशलेस ट्रांजेक्शन को लगातार बढ़ावा दे रही है। कोरोना महामारी के बाद सभी क्षेत्रों में डिजिटल कामकाज में काफी तेजी आई है। अब ज्यादातर उपभोक्ता डिजिटल बैंकिंग को काफी पसंद कर रहे हैं। लोगों का बैंकों में आना-जाना और लेनदेन करना भले ही कम हुआ है लेकिन उनका बैंकों से डिजिटल संपर्क बढ़ा है। बीते दो वर्षों में 80 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों का कैशलेस लेनदेन बढ़ा है।

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के बाद सभी क्षेत्रों में डिजिटल कामकाज में काफी तेजी आई है। इसके साथ ही डिजिटल और संपर्करहित लेनदेन भी काफी बढ़ा है। इस असर बैंकिंग क्षेत्र पर भी पड़ा है। अल्कामी टेक्नोलॉजी की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस समय 78 प्रतिशत उपभोक्ता डिजिटल बैंकिंग को प्राथमिकता दे रहे हैं। यह उपभोक्ता मोबाइल एप या वेबसाइट के जरिये डिजिटल बैंकिंग करते हैं।

रिपोर्ट की खास बातें:

- बीते दो वर्षों के दौरान 80 प्रतिशत से ज्यादा वित्तीय संस्थानों का कैशलेस लेनदेन बढ़ा है।
- 60 प्रतिशत से ज्यादा वित्तीय संस्थानों के कैशलेस लेनदेन में 20 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि रही।
- बीते तीन वर्षों में 50 प्रतिशत बैंकों ने डिजिटल सेवाएं देने के लिए फिनटेक से समझौते किए।

बैंकों से डिजिटल संपर्क बढ़ा

रिपोर्ट के अनुसार, भले ही लोगों का बैंकों में आना-जाना और लेनदेन करना कम हुआ है लेकिन उनका बैंकों से डिजिटल संपर्क बढ़ा है। मोबाइल और डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाले ग्राहक अब दैनिक आधार पर बैंकों से ज्यादा संपर्क में रहते हैं।

"जो डेटा का सर्वोत्तम उपयोग कर सकेंगे और डिजिटल उपभोक्ताओं की तेजी से बदलती जरूरतों को पूरा कर सकेंगे, वही भविष्य में बैंकिंग क्षेत्र का नेतृत्व करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल बैंकिंग अपना रहे हैं। इसका यह असर भी दिख रहा है कि अब एटीएम और बैंकों में जाने वाले लोगों की संख्या में काफी कमी दिख रही है।"

बिटकॉइन उत्पादों की भी हो रही मांग

रिपोर्ट में कहा गया है कि डिजिटल लेनदेन में तेजी के साथ बैंकों से क्रिप्टोकरेंसी की मांग भी हो रही है। 21 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों ने माना है कि उनके ग्राहकों ने उनसे बिटकॉइन उत्पादों और सेवाओं की मांग की है। वहीं, 35 प्रतिशत बैंकों का मानना है कि क्रिप्टोकरेंसी विकल्प की पेशकश करने से उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक रूप से बढ़त मिल सकती है।

तेल कंपनियों पर लगातार पांचवीं तिमाही में जुर्माना, मानदंड नहीं कर पा रहीं पूरा

एनएसई ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हिंदुस्तान पेट्रोलियम भारत पेट्रोलियम ऑयल इंडिया गेल और मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स पर अप्रैल जून तिमाही में सूचीबद्धता की आवश्यकता को पूरा नहीं करने के लिए जुर्माना लगाया है। कंपनियों ने शेयर बाजारों को अलग-अलग दी सूचना में कहा है कि निदेशकों की नियुक्ति सरकार को करनी है और इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है।

नई दिल्ली। सूचीबद्धता मानदंडों को पूरा करने में विफल रहने पर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और गैस कंपनी गेल समेत अन्य बड़ी तेल कंपनियों पर लगातार पांचवीं तिमाही में जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना अपने निदेशक मंडलों में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र और महिला निदेशकों की नियुक्ति नहीं करने को लगा है।

शेयर बाजारों बीएसई और एनएसई ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, ऑयल इंडिया, गेल और मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स पर अप्रैल-जून तिमाही में सूचीबद्धता की आवश्यकता को पूरा नहीं करने के लिए जुर्माना लगाया है। कंपनियों ने शेयर बाजारों को अलग-अलग दी सूचना में कहा है कि निदेशकों की नियुक्ति सरकार को करनी है और इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है।

नियमों के अनुसार, कंपनियों को कार्यकारी या कार्यात्मक निदेशकों के समान अनुपात में स्वतंत्र निदेशक और कम से कम एक महिला निदेशक रखने की भी आवश्यकता है। BPCL ने अपने बोर्ड में एक भी स्वतंत्र निदेशक न होने के कारण बीएसई और एनएसई से 2,41,900-2,41,900 रुपये का जुर्माना लगाए जाने की सूचना दी है। कंपनी ने निदेशक नियुक्तियों को प्रभावित करने में अपनी असमर्थता का उल्लेख किया है और बीएसई लिमिटेड तथा एनएसई दोनों से जुर्माना माफ करने की योजना का संकेत दिया है। एचपीसीएल ने पुष्टि की है कि बीएसई और एनएसई ने उस पर 5,36,900-5,36,900 रुपये का जुर्माना लगाया है।

गेल पर भी इसी तरह का जुर्माना लगाया गया है। कंपनियों ने इस बात पर जोर दिया कि गैर-अनुपालन उनके नियंत्रण से बाहर था और उनकी ओर से किसी लापरवाही के कारण नहीं था। गेल ने कहा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि बोर्ड की संरचना के संबंध में गैर-अनुपालन न तो कंपनी की किसी लापरवाही/चूक के कारण था और न ही गेल के प्रबंधन के नियंत्रण में था और अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास भी किए गए थे।

IndiGo में टिकट बुक करते समय नहीं पूछा जाएगा स्त्री हैं या पुरुष, जल्द मिलेगा नया ऑप्शन

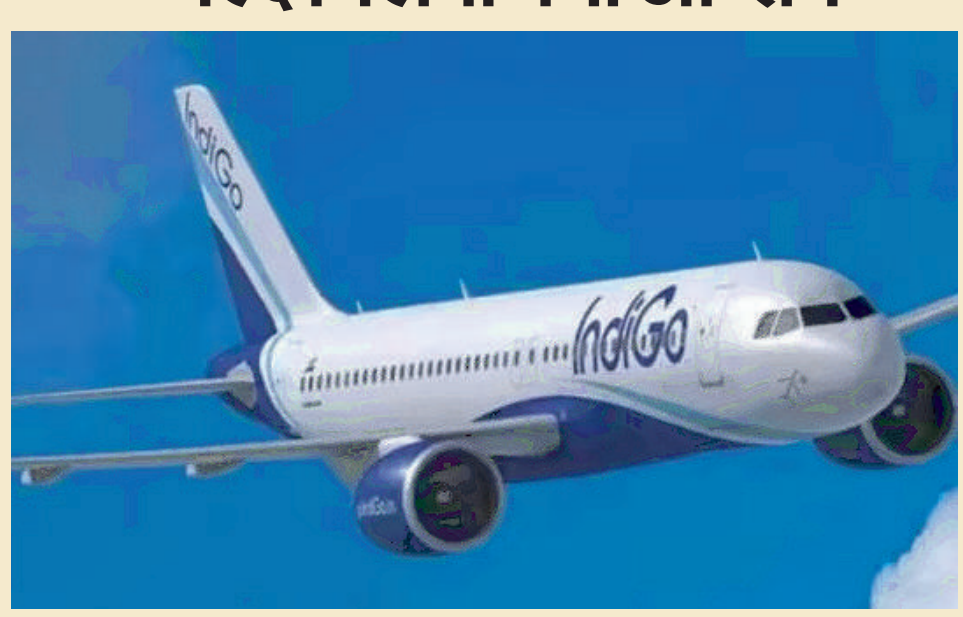

इंडिगो की घरेलू बाजार में 62 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इंडिगो के मुख्य मानव संसाधन अधिकारी सुखजीत एस पसरीचा के अनुसार एयरलाइन अपने यात्रियों के लिए बुकिंग के समय एमएक्स विकल्प पेश करेगी। इससे उन ट्रांसजेंडरों को एक विकल्प मिलेगा जो अपनी पहचान नहीं बताना चाहते। अभी बुकिंग प्रक्रिया के दौरान एयरलाइन की वेबसाइट पर पुरुष और महिला विकल्प उपलब्ध है।

नई दिल्ली। विमानन कंपनी इंडिगो जल्द ही टिकट बुकिंग के समय यात्रियों के लिए स्त्री-पुरुष तटस्थ 'एमएक्स' का विकल्प देगी। इसमें यह नहीं पूछा जाएगा कि टिकट बुकिंग करने वाला स्त्री है या पुरुष। इसके अतिरिक्त एयरलाइन का लक्ष्य अपने यहां नियुक्त विकलांग व्यक्तियों की संख्या को दोगुना करना है।

इंडिगो की घरेलू बाजार में 62 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इंडिगो के मुख्य मानव संसाधन अधिकारी सुखजीत एस पसरीचा के अनुसार, एयरलाइन अपने यात्रियों के लिए बुकिंग के समय 'एमएक्स' विकल्प पेश करेगी। इससे उन ट्रांसजेंडरों को एक विकल्प मिलेगा जो अपनी पहचान नहीं बताना चाहते। अभी बुकिंग प्रक्रिया के दौरान एयरलाइन की वेबसाइट पर पुरुष और महिला विकल्प उपलब्ध है।

एयर इंडिया एक्सप्रेस और विस्तारा पहले से ही टिकट बुकिंग के समय यात्रियों के लिए एमएक्स विकल्प देते हैं।पसरीचा ने कहा कि इंडिगो ने एलजीबीटीक्यू प्लस समुदाय के लिए कई पहल को लागू किया है, जिसमें समुदाय से जुड़े लोगों की भर्ती को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कार्यक्रम शामिल हैं। उनके अनुसार एलजीबीटीक्यू प्लस व्यक्तियों की लगातार भर्ती हो रही है। वे एयरलाइन में उड़ान सहित विभिन्न कार्यों में काम कर रहे हैं।

संस्कारशाला: श्री कृष्ण के जीवन से बच्चों और युवाओं के लिए 10 महत्वपूर्ण शिक्षाएं

- डॉ. अंकुर शरण.

श्रीकृष्ण का जीवन अनंत प्रेरणाओं से भरा है। उनका जन्म से लेकर गीता ज्ञान तक का सफर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन की हर परिस्थिति में हमारे मार्गदर्शन का स्त्रोत भी है। बच्चों और युवाओं के लिए उनके जीवन से अनेक महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिन्हें अपनाकर वे अपना जीवन सफल बना सकते हैं। आइए, श्रीकृष्ण के जीवन से 10 महत्वपूर्ण शिक्षाओं पर एक नज़र डालते हैं:

धैर्य और आत्मविश्वास

श्रीकृष्ण ने बाल्यकाल में ही कंस जैसे दुष्ट राजा से सामना किया, लेकिन कभी भी धैर्य नहीं खोया। उन्होंने दिखाया कि आत्मविश्वास और धैर्य के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है।

सच्चे मित्र बनना और निभाना

श्रीकृष्ण और सुदामा की मित्रता सच्ची मित्रता का सर्वोत्तम उदाहरण है। उन्होंने बताया कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिन समय में साथ देते हैं, और मित्रता में स्वार्थ नहीं होता।

ज्ञान की महत्ता

बालकृष्ण ने छोटी उम्र में ही विभिन्न ज्ञानों का अर्जन किया और यह साबित किया कि शिक्षा और ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। सीखने की ललक हमेशा बनाए रखनी चाहिए।

अनुशासन और संतुलन

गोकुल में बालकृष्ण ने गायों की देखभाल से लेकर माखन चोरी तक सब कामों में संतुलन और अनुशासन बनाए रखा। यह बताता है कि जीवन में अनुशासन और समय का प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण है।

दूसरों की भलाई

कालिया नाग का उद्धार हो, या गोवर्धन पर्वत उठाकर गांववालों को सुरक्षित करना, श्रीकृष्ण ने हमेशा दूसरों की भलाई को सर्वोपरि रखा। इससे बच्चों और युवाओं को दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहने की प्रेरणा मिलती है।

धर्म और कर्तव्य का पालन

महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर श्रीकृष्ण ने धर्म और कर्तव्य पालन का महत्त्व समझाया। उन्होंने बताया कि अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बिना।

संकल्प शक्ति

कंस का वध करने का संकल्प बालकृष्ण ने बचपन में ही लिया था और उसे पूरा भी किया। यह सिखाता है कि अपने लक्ष्यों के प्रति संकल्पित रहना चाहिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए।

सर्वधर्म समभाव

श्रीकृष्ण ने कभी भी जाति, धर्म या वर्ग में भेदभाव नहीं किया। उन्होंने सभी को समान दृष्टि से देखा और समान प्रेम दिया। इससे सीख मिलती है कि सभी धर्मों और जातियों का सम्मान करना चाहिए।

सकारात्मक सोच

जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी श्रीकृष्ण ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वे हमेशा सकारात्मक सोच और उत्साह से भरे रहे। इससे सीख मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक रहना चाहिए।

साहस और पराक्रम

गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के क्रोध से गांववालों की रक्षा करना या कालिया नाग को परास्त करना, श्रीकृष्ण ने साहस और पराक्रम का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। इससे बच्चों और युवाओं को साहसी बनने की प्रेरणा मिलती है।

श्रीकृष्ण का जीवन हमारे लिए एक मार्गदर्शक है। उनके जीवन की इन शिक्षाओं को अपनाकर हम न केवल एक अच्छा इंसान बन सकते हैं, बल्कि समाज और देश के लिए भी योगदान दे सकते हैं। हर बच्चे और युवा को उनके जीवन से यह सीखना चाहिए कि कैसे कठिनाइयों के बावजूद सही मार्ग पर चलते रहना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।

कविता : फ़िक्र

घर से निकला आदमी,
खुशनुमा चेहरा लिए
दिनचर्या में हुआ लीन।
भले ही इस दौरान,
सुख चैन गया हो छीन।
गर आ जाए एक कॉल,
पूछ ले अर्धांगिनी हाल।
तब आए सुकूनभरी आवाज़,
₹कैसे हो, कहां हो और
घर कब तक आओगे₹।
थकान की निद्रा को
चीरती हुई मिठास।
₹अपनेपन₹ और ₹फिक्र₹ का,
दिलाती है एहसांस।
तब बरबस ही निकलता,
संजय से एक ही संवाद
₹अरे अरे हमसफर इतने सवाल₹।
बरबस ही निकला जवाब,
₹मैं रास्ते में हूं, आ रहा हूं₹।
मन ही मन वो बुदबुदाया,
सच कितनी ₹फिक्र₹ है
तुम्हें मेरे घर आने की।

-संजय एम .तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)
व्हाट्सएप नंबर 9826025986

17 तारीख को प्रधानमंत्री ओडिशा आकर सुभद्रा योजना उद्घाटन करेंगे

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड उडीशा

भुबनेश्वर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को ओडिशा आएंगे । ओडिशा आकर सुभद्रा योजना उद्घाटन करेंगे।केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि पैसा सीधे महिलाओं के खाते में जाएगा।केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन, पुरी के सांसद संवित पान, पिपिली के विधायक आश्रित पटनायक, सतावस्त के विधायक ओम मिश्रा प्रकाश भी मंदिर गए और भगवान के दर्शन किए। हालांकि, दर्शन सारी के वापस लौटने के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया को जवाब दिया ।

उन्होंने कहा कि सुभद्रा योजना से ओडिशा की महिलाएं सशक्त होंगी । 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम का उद्घाटन करने और लाभार्थियों के खाते में राशि का भुगतान करने के लिए ओडिशा आएंगे । सरकार पुरी को अत्याधुनिक आध्यात्मिक शहर बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। केंद्रीय मंत्री धर्मवेंद्र प्रधान ने कहा कि इसी तरह मंदिर के खजाने का निरीक्षण और रत्नों की गिनती भी आने वाले दिनों में राज्य सरकार द्वारा सुचारू रूप से की जाएगी ।

सड़क सुरक्षा पर मंडराता खतरा: सड़कों पर जानवर और मवेशी

डॉ. अंकुर शरण

फरीदाबाद की सड़कों पर जानवरों और मवेशियों की बढ़ती संख्या ने सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया है। शहर के विभिन्न हिस्सों में, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में, सड़कों पर बेसहारा मवेशियों का घूमना आम बात हो गई है। यह स्थिति न केवल वाहनों के लिए बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी जानलेवा साबित हो रही है।

इस रिपोर्ट में फरीदाबाद की सड़कों पर जानवरों और मवेशियों से उत्पन्न समस्याओं और उनके समाधान के उपायों पर प्रकाश डाला गया है। इसे प्रकाशित कर अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है।

यह बात सच है कि अक्सर प्रशासन तब जागता है जब कोई अनहोनी घटना घट जाती है। सड़क सुरक्षा को लेकर यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती, तो यह एक ज्वालामुखी के समान होता है जो कब फट पड़ेगा, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ऐसी ही स्थिति इन दिनों फरीदाबाद और गुरुग्राम के रास्तों पर देखने को मिल रही है, जहां आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में या तो मवेशी मारे जा रहे हैं या फिर मवेशियों की वजह से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं।

फरीदाबाद और गुरुग्राम के रास्तों पर मवेशियों की समस्या:

फरीदाबाद और गुरुग्राम जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों की सड़कों पर मवेशियों की उपस्थिति न केवल यातायात में बाधा डाल रही है, बल्कि गंभीर दुर्घटनाओं का कारण भी बन रही है। खासकर रात के समय, जब दृश्यता कम होती है, सड़क पर अचानक मवेशियों के आ जाने से वाहन चालक दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। इन दुर्घटनाओं में न केवल मवेशियों की मौत होती है, बल्कि कई निर्दोष लोग भी अपनी जान गंवा बैठते हैं।

साइड इफेक्ट्स:

दुर्घटनाओं में वृद्धि: सड़कों पर अचानक मवेशियों के आ जाने से वाहन चालक हड़बड़ी में नियंत्रण खो बैठते हैं, जिससे गंभीर दुर्घटनाएं होती हैं। कई बार, इन दुर्घटनाओं में जान-माल का भारी नुकसान होता है।

यातायात में बाधा: मवेशियों के सड़कों पर होने से यातायात में रुकावट आती है, जिससे लंबा जाम लग जाता है। यह न केवल समय की बर्बादी का कारण बनता है बल्कि आपातकालीन सेवाओं के लिए भी गंभीर चुनौती पेश करता है।

पर्यावरणीय खतरे: मवेशियों के सड़क पर होने से कचरा फैलता है, जिससे स्वच्छता की समस्या उत्पन्न होती है। इसके साथ ही, मवेशियों के चलते सड़कों पर गोबर और अन्य गंदगी का जमाव होता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं।

वाहनों की क्षति: मवेशियों से टकराने के कारण वाहनों की क्षति होती है, जिससे वाहन मालिकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।

समस्या का समाधान:

सख्त कानून लागू करें: स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि वह सड़कों पर बेसहारा मवेशियों को छोड़ने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इसके लिए जुर्माने और सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए।

पशु आश्रय का निर्माण: मवेशियों के लिए विशेष पशु आश्रय स्थलों का निर्माण किया जाना चाहिए, जहां उन्हें भोजन और देखभाल मिल सके। इससे मवेशियों को सड़क से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सकेगा।

जागरूकता अभियान: लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए, जिससे वे समझ सकें कि मवेशियों को सड़कों पर छोड़ने से कितनी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

सीसीटीवी निगरानी: सड़कों पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे कि मवेशियों को छोड़ने वालों की पहचान की जा सके और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

समुदाय की भागीदारी: स्थानीय समुदायों को भी इस समस्या के समाधान में शामिल किया जाना चाहिए। उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे अपने मवेशियों को सड़कों पर न छोड़ें और सुरक्षित स्थान पर रखें।

फरीदाबाद की सड़कों पर जानवरों और मवेशियों की उपस्थिति सड़क सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। इसे रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन, समुदाय और व्यक्तियों को मिलकर काम करना होगा। सख्त कानून, जागरूकता अभियान, और पशु आश्रय स्थलों के निर्माण से इस समस्या का समाधान संभव है। यह आवश्यक है कि हम सभी मिलकर इस दिशा में ठोस कदम उठाएं ताकि सड़कों को सुरक्षित बनाया जा सके और दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।

"सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ डॉ. अंकुर शरण का विशेष कार्यक्रम"

डॉ. अंकुर शरण, जो न केवल एक अनुभवी लॉजिस्टिशियन हैं बल्कि सड़क सुरक्षा के भी विशेषग्य हैं, ने सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम स्थापित किया है। इस कार्यक्रम को विभिन्न स्टेकहोल्डर्स और रोड सेफ्टी टीम की मदद से संचालित किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम के तहत, डॉ. शरण और उनकी टीम सड़क दुर्घटनाओं के कारणों का गहन अध्ययन कर रहे हैं और इससे बचने के लिए आवश्यक एहतियातों और उपायों पर काम कर रहे हैं। वे सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसमें सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने का कार्य भी शामिल है।

यदि आपके पास इस विषय पर कोई सुझाव या विचार हैं, तो कृपया निम्नलिखित ईमेल आईडी पर संपर्क करें:
roadsafetysquad@gmail.com

आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और सड़क सुरक्षा के प्रति हमारी इस मुहिम को और अधिक सशक्त बनाने में सहायक हो सकते हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095 . newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी .आर .बी . एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023